शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित
राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 12 | अंक : 223 | गुवाहाटी | गुरुवार, 19 मार्च, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

पांच चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर — पेज 2
राज्य सरकार ने विकास के नए कीर्तिमानों का एक नया दौर लिखा : असम भाजपा — पेज 3
मुख्यमंत्री ने लांच की तीन बड़ी औद्योगिक नीतियां, निवेशकों को दिया आमंत्रण — पेज 5
हॉकी विश्व कप : चुनौतीपूर्ण पूल डी में भारत कोच मारिजने बोले- प्रदर्शन... — पेज 7

प्रियंका गांधी ने बरदलै के बाहर निकलने पर कहा

काश हमने बात कर ली होती

नई दिल्ली। नगांव के सांसद प्रद्युत बरदलै के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने से नई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, कांग्रेस नेतृत्व ने इस कदम को *दुर्भाग्यपूर्ण* बताया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बरदलै का इस्तीफा अफसोसजनक है, और उन्होंने संकेत दिया कि टिकट आवंटन को लेकर मतभेद उनके इस फैसले का कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वह टिकट आवंटन को लेकर नाराज थे, और काश हमें बातचीत करने का मौका मिलता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, वाड्रा ने संसद भवन परिसर के अंदर पत्रकारों से कहा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि नगांव सांसद का भगवा खेमे में शामिल होना विचारधारा के साथ समझौता करने के बराबर है और यह *सही नहीं* है। -शेष पृष्ठ दो पर

चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका प्रद्युत बरदलै हुए भाजपा में शामिल

गुवाहाटी। असम के लोकसभा सांसद प्रद्युत बरदलै बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। विपक्षी कांग्रेस को करारा झटका देते हुए, प्रद्युत बरदलै ने राज्य में विधानसभा चुनाव से महज 20 दिन पहले मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने पर सांसद प्रद्युत बरदलै ने कहा कि इसका कोई एक कारण नहीं है। -शेष पृष्ठ दो पर

समुदायों की उपेक्षा करती है पार्टी : प्रद्युत

गुवाहाटी/नई दिल्ली (हि.स.)। पूर्व कांग्रेस सांसद प्रद्युत बरदलै ने बुधवार को भाजपा में शामिल होने के बाद अपनी पूर्व पार्टी कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस में जनजातियों और विभिन्न समुदायों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रद्युत बरदलै ने कहा कि कांग्रेस की -शेष पृष्ठ दो पर

पार्टी के भीतर मतभेद नहीं, बरदलै का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण : गौरव

नई दिल्ली। सांसद प्रद्युत बरदलै के इस्तीफे को लेकर असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बुधवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, किसी भी पार्टी के अंदर मतभेद होते हैं। हम सभी ने मतभेदों का सामना किया है और अपनी मजबूत राय रखी है। मुझे नहीं लगता कि एक सीट को लेकर मतभेद किसी पार्टी को छोड़कर विरोधी दल में जाने की वजह हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, दो दिन पहले ही मैं लखीमपुर जिले में था, जहां भूपेन बोरा इस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से टिकट मांग रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी है, साथ ही संगठन की ताकत भी बढ़ी है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी असम के लोगों के विचार और इच्छा के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी अगली सरकार -शेष पृष्ठ दो पर

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

परीक्षा करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है।

– आचार्य चाणक्य

असम चुनाव : भाजपा की रणनीति को अंतिम रूप

पीएम करेंगे तीन रैली और शाह का होगा आक्रामक प्रचार

नई दिल्ली/गुवाहाटी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने असम के लिए अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है, एनडीए के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का समझौता कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण की तैयारी कर रही है। समझौते के अनुसार, भाजपा 89 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद 26 सीटों पर और बोड़ोलैंड पीपुल्स फ्रंट 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। आंतरिक विचार-विमर्श के बाद सीटों का बंटवारा तय किया गया है और पार्टी सूत्रों के अनुसार अब उम्मीदवारों की घोषणा और चुनाव प्रचार की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी असम में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे, जिनकी संभावित तिथियां 1, 3 और 6 अप्रैल हैं। भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से इन रैलियों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्रित करने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मार्च महीने में असम भर में आक्रामक चुनाव प्रचार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और जनसंपर्क प्रयासों को मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रही है, और सूत्रों का कहना है कि अधिकांश सीटों के लिए जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पार्टी अगले दो दिनों के भीतर उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, टिकट वितरण एक संवेदनशील प्रक्रिया बनी हुई है, जिसका परिणाम स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। आंतरिक चर्चाओं में 2027 में प्रस्तावित परिसीमन पर भी बात हुई है, जिसके बारे में पार्टी नेताओं का मानना है कि राज्य में इसके दीर्घकालिक राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने और शीर्ष नेतृत्व के सक्रिय होने के बाद, भाजपा असम में रणनीति से क्रियान्वयन की ओर तेजी से बढ़ रही है। असम की सभी 126 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को घोषणा की कि असम गण परिषद (अगप) 26 सीटों पर, बोड़ोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) 11 सीटों पर और शेष सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज हमने अपनी पार्टी सूची के संबंध में शुरुआती चर्चा की। कल हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक है। मुझे लगता है कि सूची कल देर रात या परसों सुबह घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं (कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले असम के सांसद) प्रद्युत बरदलै के संपर्क में नहीं हूं। अगर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की होती, तो मुझे पता -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 86.5 प्रतिशत की कमी : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 86.5 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म *एक्स* पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए निरंतर उपाय किए हैं, हालांकि ऐसे मामलों को पूरी तरह से समाप्त करने तक प्रयास जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं और बहनों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी कमी आई है। लेकिन हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि एक दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध शून्य हो जाएं। शर्मा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ -शेष पृष्ठ दो पर

प्रद्युत बरदलै ने अमित शाह से की मुलाकात

नई दिल्ली (हि.स.)। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद प्रद्युत बरदलै ने लोकसभा सदस्य से इस्तीफा देकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर प्रद्युत बरदलैने कहा कि उन्हें कांग्रेस में घुटन -शेष पृष्ठ दो पर

बिहू से पहले आ सकते है एचएसएलसी के नतीजे

गुवाहाटी। असम राज्य के लाखों छात्रों को राज्य के दो प्रमुख आयोजनों – आगामी विधानसभा चुनाव और रोंगाली बिहू के उत्सव – से पहले अपने एचएसएलसी परीक्षा परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (एएसएसईबी) मूल्यांकन प्रक्रिया को अपने सामान्य समय-सीमा से काफी पहले पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की है, लेकिन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में काफी पहले घोषित किए जाएंगे। 2025 में एचएसएलसी के परिणाम 11 अप्रैल को घोषित किए गए थे। एएसएसईबी के परीक्षा नियंत्रक नयन ज्योति शर्मा ने कहा कि इस वर्ष उम्मीदवारों -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

नेपाल में जेन जी प्रदर्शन के दौरान जेल तोड़कर भागे 1200 कैदी अभी भी फरार

काठमांडू (हि.स.)। जेनजी आंदोलन के दौरान पिछले साल 9 सितंबर को सुन्धारा स्थित केंद्रीय कारागार से भागे एक हजार दो सौ से अधिक कैदी अब भी फरार हैं। केंद्रीय कारागार कार्यालय के सूचना अधिकारी बैकुंठ रेग्मी के अनुसार 9 सितंबर की सुबह तक केंद्रीय कारागार में कुल 3,880 कैदी थे। उसी दिन 3,517 कैदी भाग गए थे। उनमें से अधिकांश को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 1,200 कैदी फरार हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केंद्रीय कारागार में कुल 3,313 कैदी मौजूद हैं। इनमें 1,920 सजायाफ्ता कैदी और 1,493 विचाराधीन बंदी शामिल हैं।

पालम अग्निकांड : एक ही रास्ते ने ली 9 जिंदगियां

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली का पालम इलाका बुधवार सुबह उस वक्त चीख-पुकार और अफरा-तफरी से भर गया, जब साध नगर की गली नंबर-2 स्थित एक चार मंजिली इमारत में भीषण आग लग गई। सुबह लगी इस आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें तीन मासूम बच्चियां भी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस वक्त आग लगी उस समय इमारत में रह रहे अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था, जो बाहर निकलने का जरिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वहीं सबसे ज्यादा आग भड़क रही थी। कुछ ही देर में कमरों में जहरीला धुआं भर गया, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। बालकनियों -शेष पृष्ठ दो पर

एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के बाद इंतजार करें वितरणकर्ताओं के यहां लाइन लगाने से बचें : सरकार

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की बुकिंग के बाद इंतजार करें और वितरणकर्ताओं के यहां लाइन लगाने से बचें। वर्तमान में एलपीजी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं बुकिंग के लिए अब 93 प्रतिशत लोग ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और गैस का उचित उपयोग करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही कीमतें बढ़ रही हों, फिलहाल भारत में डीजल-पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बुधवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि कच्चे तेल की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही है। -शेष पृष्ठ दो पर

सेवानिवृत्ति अंत नहीं नई जिम्मेदारियों की शुरुआत : राधाकृष्णन

नई दिल्ली (हि.स.)। राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने आगामी अप्रैल से जुलाई के बीच अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो रहे 59 सांसदों को विदाई देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति को अंत नहीं, बल्कि नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। सभापति ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार हर दो वर्ष में सदन के एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते -शेष पृष्ठ दो पर

तेल अवीव में ईरान का 100 से अधिक स्थानों पर हमला

तेल अवीव (हि.स.)। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने ईरान के पूर्व शीर्ष सुरक्षा अधिकारी डॉ. अली लारीजानी की हमले में मौत के बाद इजराइल के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की है। आईआरजीसी ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। डॉ. लारीजानी की मौत अमेरिका-इजराइल के एकीकृत सैन्य अभियान में हुई है। अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का आज 19वां दिन है। ईरान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी आईआरजीसी के बयान में दी गई। आईआरजीसी ने कहा है कि उसने अमेरिका-इजराइल की आक्रामकता के जवाब में अपने ऑपरेशन *ट्रू प्रॉमिस 4* की 61वीं लहर के दौरान इन ठिकानों पर हमला किया। बयान में कहा गया कि दुश्मन ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मल्टी-वॉरहेड -शेष पृष्ठ दो पर

राजनीति में *फुल स्टॉप* नहीं होता, जनसेवा सदन के बाहर भी जारी रहती है : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अप्रैल से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त हो रहे राज्यसभा के 59 सदस्यों को विदाई देते हुए कहा कि राजनीति में कभी *पूर्ण विराम* नहीं होता और जनसेवा का कार्य सदन के बाहर भी निरंतर जारी रहता है। उन्होंने कहा कि संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि एक *ओपन यूनिवर्सिटी* है, जहां हर सदस्य को सीखने, विचार साझा करने और खुद को विकसित करने का अवसर मिलता है। राज्यसभा में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं में हर सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यकाल के दौरान खट्टे-मीठे अनुभव भी सामने आते हैं, लेकिन विदाई के समय सभी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर एक समान भावना व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदाई ले रहे कुछ सदस्य भविष्य में फिर से सदन में लौट सकते हैं, जबकि कुछ अपने अनुभवों के आधार पर सामाजिक जीवन में नए योगदान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो सदस्य जा रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव राष्ट्र जीवन में हमेशा उपयोगी रहेगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एचडी देवगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार आदि वरिष्ठ नेताओं के योगदान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि लंबे संसदीय अनुभव वाले नेताओं से नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा संसदीय कार्यप्रणाली को समर्पित -शेष पृष्ठ दो पर

ड्रोन हमलों का खौफ

दुबई समेत पूरे यूएई में सिर्फ मस्जिदों के अंदर होगी ईद की नमाज

नई दिल्ली। अमेरिका-इजराइल और ईरान में चल रहे जंग के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार सुरक्षा कारणों के चलते ईद-उल-फितर की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर अदा की जाएगी। जनरल अथॉरिटी फॉर इस्लामिक अफेयर्स, एंडोमेंट्स एंड जकात ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। यूएई की सुरक्षा अथॉरिटी के मुताबिक, सुरक्षा कारणों के चलते यह फैसला लिया गया है। यूएई में इस साल ईद-उल-फितर की नमाज सिर्फ मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। दुबई और शारजाह समेत पूरे यूएई में खुले ईदगाहों या बाहरी मैदानों में नमाज नहीं होगी। लोगों को मस्जिद में जल्दी आने और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

अखिल गोगोई 20 को दाखिल करेंगे नामांकन

शिवसागर (हिंस)। असम की क्षेत्रीय पार्टी राइजर दल के नेताओं ने बुधवार को शिवसागर में रिटर्निंग ऑफिसर से पार्टी विधायक अखिल गोगोई के नामांकन पत्र लिए। इस प्रक्रिया के दौरान पार्टी के केंद्रीय और जिला, दोनों स्तरों के पदाधिकारी मौजूद थे, जिससे शिवसागर विधानसभा क्षेत्र से गोगोई के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत का संकेत मिला। इस दौरान पार्टी नेताओं ने बताया कि अखिल गोगोई 20 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राइजर दल के एकमात्र विधायक अखिल गोगोई, जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा में किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल में जमीनी मुद्दों से लगातार जुड़ाव देखने को मिला है, जिससे पार्टी का मानना है कि इस क्षेत्र में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है।

भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक

पांच चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर

नई दिल्ली (हि.स.)। असम, पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। बुधवार शाम भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस सहित समिति के सदस्य पहुंचे। इस अहम बैठक में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव और केरल के लिए भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। बुधवार को असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी की अधिकतर सीटों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ पश्चिम बंगाल की बची हुई 149 सीटों पर अंतिम फैसला होगा। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में असम के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पदुचेरी के विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में केरल और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के कई नामों पर मुहर लगी थी। भाजपा पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इसी तरह केरल के लिए भी 47 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है।

त्रिपुरा में युसुफ काउंसिल का चुनाव 13 अप्रैल को होगा : राज्य चुनाव आयोग

अगरतला। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वय जिला परिषद (टीटीएडीसी) का चुनाव 13 अप्रैल को होगा। मंगलवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि 28 सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि विपक्ष की गिनती 17 अप्रैल को होगी। चुनाव संबंधी आधिकारिक अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवार 25 मार्च तक अपना नामांकन नामांकन कर सकते हैं। नामांकन नामांकन की जांच 26 मार्च को की जाएगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। आयोग ने यह भी घोषणा की कि जनजातीय परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रभाव लागू किया जाएगा। कुमार ने राजनीतिक विचारधारा से इंडिपेंडेंट, सिविल और एलसीटी का पालन करने का आग्रह किया। काउंसिल का वर्तमान पद 18 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। वर्तमान परिषद में टिपरा मोथा पार्टी के पास 19 सदस्यीय बहुमत है, जबकिभारतीय जनता पार्टी के पास नौ सदस्य हैं। राज्यपाल द्वारा दो अतिरिक्त सदस्यों का मनोनीत किया गया है। कुमार ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सभी आंशिक पूर्ण मतदान और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाएगी। पुलिस कर्मचारी अनुराग ने कहा कि वोटिंग में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी ताकि कलाकार बिना किसी डर या खतरे के अपने फ्रैंचाइजी का उपयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि काउंसिल में सभी 1,257 वोटिंग आवेदकों को पासपोर्ट के लिए सुरक्षा आधार पर नियुक्त किया गया है। इनमें से 311 बूथ उच्च गंभीर श्रेणी (ए) के अंतर्गत आते हैं, 693 मध्यम खतरे के खतरे (बी) के अंतर्गत आते हैं, और 253 को सामान्य के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस, टीआईआर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लगभग 11,000 लोगों को तैनात किया जाएगा।

रास चुनाव में राजद का उम्मीदवार पिछड़ा : विधायक सुरेंद्र प्रसाद

पश्चिम चम्पारण (हिंस)। सोलह मार्च को राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक समाज से नहीं आते हैं। राजद का घोषित उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह अगड़ी जाति से आते हैं, जो महागठबंधन के मापदंड के हिसाब से सटीक नहीं बैठ रहे थे, जिनलोगों ने हमारी विधान सभा चुनाव में जीत के लिए वोट दिया ही नहीं उनको मैं क्यों वोट देता, इसलिए मेरी जमीर अनुमति नहीं दी, कि अमरेंद्र धारी सिंह को वोट दूं। उक्त बातें वाल्मीकिनगर विधान सभा के विधायक सुरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा ने बगहा नगर परिषद स्थित लशकुश मैरिज के सभागार में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा या दलित समाज से प्रत्याशी दिया रहता तो मैं निश्चित वोट करता। राजद को चाहिए था कि व्यवसायी अमरेंद्र धारी सिंह के जगह पर दीपक यादव, हिना खां, मुकेश सहनी के बीच से किसी को प्रत्याशी बनाना, परन्तु राजद ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं चुनाव के पहले हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ कोई बैठक नहीं कि गई।

जोधपुर में गुरुवार से बंद रहेगी शराब की दुकानें जिला कलेक्टर को सौंपेंगे दुकानों की चाबियां

जोधपुर (हिंस)। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में शराब दुकानदारों और पुलिस के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बढ़ते विवाद के बीच लिकर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने बड़ा फैसला लेते हुए 19 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए शराब की दुकानें बंद रखने का एलान किया है। यूनियन ने पुलिस पर बेवजह परेशान करने और कारोबार में दखल देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदारों ने निर्णय लिया है कि वे गुरुवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी दुकानों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपेंगे। यूनियन अध्यक्ष तेजाराम चौधरी ने बताया कि वर्तमान हालात में दुकानों का संचालन करना संभव नहीं रह गया है। एक ओर राज्य सरकार गारंटी के नाम पर राजस्व वसूली का दबाव बना रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस का रवैया दुकानदारों और ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इससे दुकानों की बिक्री पर सीधा असर पड़ा है और अधिकांश दुकानें घाटे में चल रही हैं। दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस शराब दुकानों के संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। ग्राहकों की गाड़ियों के चालान बनाए जा रहे हैं और कई मामलों में उन्हें शांतिभंग के आरोप में पकड़कर बंद भी किया जा रहा है। इससे ग्राहकों में भय का माहौल बन गया है और वे दुकानों तक आने से बच रहे हैं। इसके अलावा पुलिस निर्धारित समय से पहले ही दुकानों के बाहर खड़ी हो जाती है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है।

पृष्ठ एक का शेष

काश हमने बात ...

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने 65 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाली सीट से जीत हासिल की। आपने भाजपा के खिलाफ वोटों के बल पर जीत दर्ज की है। विचारधारा से समझौता करना उचित नहीं है। हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, मसूद ने कहा। इसी बीच, भाजपा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि यह इस्तीफा सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बढ़ते समर्थन को दर्शाता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अब कुछ बचा ही नहीं है। गौरव गोगोई अगला हो सकता है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जनता का विश्वास बढ़ा है, और साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस अब एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में सिमटती जा रही है क्योंकि उसके नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि कोई भी डूबती नाव पर नहीं रहना चाहता। पार्टी की कमजोरियों के कारण कांग्रेस नेता बेहतर विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए, बरदलै ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए, राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक 20 दिन पहले। इससे पहले, एआईसीसी के जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में बरदलै ने विधायक डॉ. आसिफ नजर को इस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने के कांग्रेस के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि अप्रैल 2025 में उन पर हुए जानलेवा हमले के पीछे नजर का हाथ था।

चुनाव से पहले कांग्रेस ...

मुझे घुटन महसूस हो रही थी और मेरा अपमान हो रहा था। बरदलै ने कहा कि 13 मार्च को असम केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक हुई। मुझे पता चला कि इमरान मसूद जैसे सांप्रदायिक नेता ने कहा कि जिस उम्मीदवार के खिलाफ मैंने आपराधिक सांठगांठ के सबूत दिए थे, उसके बारे में मैं जो कुछ भी कह रहा था, वह सब झूठ और मनगढ़ंत था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में इमरान मसूद ने यह कहने की धृष्टता की कि प्रद्युत बरदलै ने जो कुछ भी कहा वह सब मनगढ़ंत था। वहां मौजूद एपीसीसी अध्यक्ष चुप रहे। इससे मुझे बहुत आहत हुआ। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि नागांव से मौजूदा सांसद प्रद्युत बरदलै भाजपा में शामिल हो गए हैं...कांग्रेस पार्टी के साथ उनका रिश्ता 1975 से है; भाजपा में उनके शामिल होने से भाजपा मजबूत होगी। हम सभी उनका पार्टी में स्वागत करते हैं। असम प्रदेश भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को सिफारिश करेगी कि वे विधानसभा चुनाव लड़ें। आत्मसम्मान वाले व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी में रहने का कोई कारण नहीं है। हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लाना है। शर्मा ने आगे कहा कि नवज्योति तालुकदार और अन्य कई लोग गुवाहाटी में भाजपा में शामिल होंगे। हम आज शाम उम्मीदवारों की अपनी पार्टी सूची को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। अन्य लोग अगले दो-तीन दिनों में असम में ही शामिल हो जाएंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इमरान मसूद कौन है, यह जानने के लिए मुझे गूगल पर सर्च करने में समय लगेगा।

समुदायों की उपेक्षा ..

उपेक्षापूर्ण नीति के कारण विभिन्न समुदाय उससे दूर हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को नजरअंदाज किया, जिसके चलते उसका जनाधार कमजोर होता गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी की परवाह नहीं करती। सभी समुदायों को नजरअंदाज करने की वजह से आज उसकी यह स्थिति हो गई है। सांसद प्रद्युत बरदलै ने आगे कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और जमीनी स्तर के लोगों के बीच दूरी लगातार बढ़ती गई, जिसके कारण नेता और समर्थक पार्टी से दूर होते चले गए। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने पार्टी पर कई अन्य आरोप लगाए।

पार्टी के भीतर मतभेद ...

बनाएगी। गोगोई ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। महज दो साल पहले कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नगांव से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया था। वह मौजूदा सांसद हैं। नगांव की जनता ने उन्हें वोट दिया था। मौजूदा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके परिवार के एक सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इस तरह परिवार को एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा फैसला लिया। यह उनका निजी फैसला है। यह चुनाव एक व्यक्ति से कहीं अधिक अहम है। उन्होंने कहा कि यह हिमंत विश्व शर्मा के चंगुल से असम को मुक्त कराने का चुनाव है। असम को हिमंत विश्व शर्मा की डर और धमकी की राजनीति से मुक्त कराने का चुनाव है। इसलिए असम की जनता हिमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती है। हमें जबरदस्त समर्थन मिला है। हमें पूरा भरोसा है कि हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौरव गोगोई का स्वागत किया। समर्थकों ने नारे लगाए और फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए, खासकर जमीन से जुड़े घोटालों और प्रशासनिक अनियमितताओं का जिक्र किया। गोगोई ने कहा कि राज्य सरकार विकास के नाम पर जनता के हितों की अनदेखी कर रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी दो दिन पहले ही मैं लखीमपुर जिले में था। यह वही जिला है, जहां से भूपेन बोरा इस समय भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता में, साथ ही कांग्रेस पार्टी की संगठन शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी असम की जनता के विचारों और इच्छाओं के अनुरूप काम कर रही है। वहां के लोग *माफिया राज, नशा राज, सिंडिकेट राज* और हिमंत विश्व शर्मा के भ्रष्ट शासन का अंत देखना चाहते हैं।

पीएम करेंगे तीन रैली...

होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक किसी भाजपा नेता से बात की है। इसकी संभावना है कि हम प्रद्युत बरदलै से संपर्क कर सकें। इससे पहले, मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया था कि यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जबकि बीपीएफ गठबंधन में बना रहेगा। यूपीपीएल और बीपीएफ बोड़ोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) में प्रतिद्वंद्वी दल हैं। यह क्षेत्र राज्य का एक स्वायत्त इलाका है। इसे 2003 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त बनाया गया था। बीटीसी क्षेत्र से 15 विधायक विधानसभा में भेजे जाते हैं। शर्मा ने कहा था कि भाजपा, असम गण परिषद (अगप) और बीपीएफ के बीच सीटों का बंटवारा तय हो चुका है और दोपहर बाद घोषणा की जा सकती है कि कौन-सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि यूपीपीएल 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हमारा गठबंधन बीपीएफ के साथ है। 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नौ अप्रैल को होंगे और मतगणना चार मई को की जाएगी। यूपीपीएल राज्य में पूरे पांच साल तक गठबंधन सरकार का हिस्सा रही, जबकि बीपीएफ ने बाद में समर्थन दिया था। दोनों दलों के मंत्री राज्य कैबिनेट में शामिल हैं। बीपीएफ 2016 में बनी पिछली भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का भी हिस्सा थी। उससे पहले 2006 से बीपीएफ कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकारों की सहयोगी रही थी। बीपीएफ 2005 में बीटीसी के गठन के बाद से सत्ता में रही थी, लेकिन 2020 में यूपीपीएल ने उसे हटा दिया था। हालांकि, 2025 में परिषद चुनावों में बीपीएफ ने फिर से सत्ता हासिल कर ली। शर्मा ने बताया कि अगप 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जो पिछली विधानसभा चुनाव में लड़ी गई सीटों के बराबर है। सीट बंटवारे के तहत बीपीएफ को 11 सीटें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम हमारी संसदीय बैठक के बाद हम सीटों के लिए नामों का एलान कर सकते हैं। भाजपा, अगप और बीपीएफ ने अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार के नाम का एलान नहीं किया है। वर्तमान विधानसभा में 126 सदस्यों में से सत्तारूढ़ भाजपा के पास 64 विधायक हैं, जबकि उसके सहयोगी अगप के पास 9, यूपीपीएल के पास 7 और बीपीएफ के पास 3 विधायक हैं। विपक्ष में कांग्रेस के पास 26 सदस्य, एआईयूडीएफ के 15 विधायक और सीपीआई(एम) का एक विधायक है। एक निर्दलीय विधायक भी है।

राज्य में महिलाओं के...

अपराधों में 86.5 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसका श्रेय उन्होंने मजबूत कानून प्रवर्तन और लक्षित हस्तक्षेपों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अधिकारियों ने कहा कि असम पुलिस ने हाल के वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज किया है, जिसमें मामलों की तेजी से जांच, गश्त में वृद्धि और अपराधों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान शामिल हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहलें भी शुरू की हैं, जिनमें महिला पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना, समर्पित कर्मियों की तैनाती करना और बेहतर निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। शर्मा ने दोहराया कि अपराध के आंकड़ों में गिरावट उत्साहजनक है, लेकिन सरकार पूरे राज्य में महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना समग्र सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है और प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगा। मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन के परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के बीच आई है।

प्रद्युत बरदलै ने ...

महसूस हो रही थी और उनका लगातार अपमान किया जा रहा था। भाजपा में जुड़ने के बाद प्रद्युत बरदलै ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मडिया से बातचीत में प्रद्युद बरदलै ने कहा कि अमित शाह से आज मुलाकात की। वे बहुत विनम्र और मददगार हैं। अमित शाह ने उन्हें असम विधानसभा चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। बरदलै ने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वे सोच-विचार करके निर्णय लेंगे। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने भी अमित शाह से मुलाकात की। उम्मीद है कि असम विधानसभा के लिए भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। हिमंत विश्व शर्मा ने पहले जानकारी दी कि पार्टी 126 विधानसभा सीटों में से 89 पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 37 में से असम गण परिषद (अगप) 26 सीटों पर, बोड़ोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होंगे। नतीजे 4 मई को आएंगे।

बिहू से पहले आ...

की रिकॉर्ड संख्या के बावजूद, मूल्यांकन कार्य पूरा होने के करीब है। इस वर्ष एचएसएलसी परीक्षा में 43.8 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए, जो बोर्ड के इतिहास में सबसे अधिक है। यह एक विशाल आयोजन था, लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया का लगभग 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है, शर्मा ने कहा। हमें विश्वास है कि परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में बहुत पहले घोषित किए जाएंगे ताकि छात्रों को देश में कहीं भी उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने का पर्याप्त समय मिल सके। राज्य भर में कुल 45 मूल्यांकन केंद्र वर्तमान में शेष कार्य को पूरा करने और परिणाम प्रसंस्करण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए त्वरित गति से काम कर रहे हैं। बोर्ड के सूत्रों ने संकेत दिया कि लक्ष्य मार्च के अंत तक परिणाम घोषित करना है, हालांकि घोषणा अप्रैल के पहले सप्ताह के पहले पखवाड़े तक भी बढ़ सकती है। इस वर्ष की एचएसएलसी परीक्षाएं 10 फरवरी से 27 फरवरी तक असम के 1,046 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गईं। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि परिणामों की औपचारिक घोषणा से पहले कई तकनीकी चरण शेष हैं। अनुपस्थित उम्मीदवारों के सत्यापन से संबंधित कार्य सबसे जटिल कार्यों में से एक है। मूल्यांकन और परिणाम घोषित होने के बीच कई काम बाकी रहते हैं। अनुपस्थिति का सत्यापन विशेष रूप से कठिन है। कुछ छात्र एक या दो विषयों में अनुपस्थित रहे हैं, और कुछ तो पूरी तरह से अनुपस्थित रहे हैं। इन मामलों का सत्यापन करना, डेटा संकलित करना और परिणाम की अंतिम गणना करना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है, शर्मा ने आगे कहा। पिछले साल भी, एएसएसईबी ने सीबीएसई के निर्धारित समय से पहले एचएसएलसी के परिणाम घोषित किए थे, और अधिकारियों ने संकेत दिया कि बोर्ड इस वर्ष भी समय पर परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने अगले शैक्षणिक कदम की योजना बना रहे छात्रों के लिए अनिश्चितता को कम किया जा सके।

एलपीजी सिलेंडर बुकिंग ...

घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की कमी की कोई खबर नहीं है और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों के लिए, आर्मेनिया और अजरबैजान की भूमि सीमा से यात्रा करने के संबंध में एक सलाह जारी की है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सुगम सीमा पार आवागमन के लिए अपनी सुविधानुसार इस सलाह का पालन करें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। दोनों नेताओं ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने पर जोर दिया और शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी भारतीय पोत सुरक्षित हैं और कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। पिछले 24 घंटों में विभिन्न बंदरगाहों से साइन-ऑफ के बाद 25 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस भेजा गया। 24म7 नियंत्रण कक्ष ने 125 कॉल और लगभग 450 ईमेल संभाले, जिनका तुरंत समाधान किया गया। एलपीजी वाहक शिवालिक और नंदा देवी आवश्यकतानुसार माल उतार रहे हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह पर अतिरिक्त 2,500 वर्ग मीटर स्थान से संचालन में सहायता मिल रही है। किसी भी बंदरगाह पर भीड़भाड़ की सूचना नहीं है।

सेवानिवृत्ति अंत नहीं ...

हैं, जिससे सदन की कार्यप्रणाली में निरंतरता बनी रहती है और नए सदस्यों को अपने विचार रखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो अनुभव और नई ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखती है। सेवानिवृत्ति अंत नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारियों की शुरुआत है। यह परंपरा नए सदस्यों को अवसर देने के साथ-साथ अनुभवी सदस्यों के मार्गदर्शन को भी बनाए रखती है। सेवानिवृत्त सदस्य अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से आगे भी सार्वजनिक जीवन में योगदान देते रहेंगे। विदाई भाषण में सभापति ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के योगदान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों और ग्रामीण भारत से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से सदन में उठाया। उनके अनुभव और किसानों एवं ग्रामीण समुदायों के प्रति प्रतिबद्धता ने सदन की चर्चाओं को समृद्ध किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि खड़गे ने संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया। इसके साथ ही उपसभापति हरिवंश के कार्यकाल की सराहना करते हुए सभापति ने कहा कि उन्होंने सदन का संचालन गरिमा, निष्पक्षता और धैर्य के साथ किया और सभी दलों का सम्मान अर्जित किया। सभापति ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य अपने-अपने राज्यों और समुदायों की आकांक्षाओं के सशक्त प्रतिनिधि रहे हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया है। उन्होंने तमिल के एक भावपूर्ण वाक्य का उल्लेख करते हुए कहा कि अच्छे कार्य समय के बाद भी जीवित रहते हैं और सदस्यों का योगदान सदन की विरासत का हिस्सा बना रहेगा। सभापति ने सभी सेवानिवृत्त सदस्यों के स्वस्थ, सुखद और सफल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वे आगे भी राष्ट्रसेवा में सक्रिय रहेंगे।

तेल अवीव में ईरान...

वाली खुर्रमशहर-4 और कद्र मिसाइलों के साथ-साथ इमाद और खैबर शिकन प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया। यह हमला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पूर्व सचिव डॉ. लारीजानी की मौत का बदला लेने के लिए किया गया। प्रेस टीवी के अनुसार, इस हमले में इजराइल की बेहद आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों के ध्वस्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप तेल अवीव में आंशिक ब्लैक आउट हो गया। इस वजह से इजराइल की सेना को मौजूदा हालात पर काबू पाने और प्रभावित लोगों को बचाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस बीच, कॉर्प्स ने बताया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अब तक 230 से ज्यादा इजराइलियों की मौत हो चुकी है। आईआरजीसी के अनुसार, तेल अवीव के अलावा पवित्र शहर अल-कुद्स, बंदरगाह हाइफ़ा, बीर शेवा और नेगेव रेगिस्तान में संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी चौकियों पर हमला किया गया। सीएनएन चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा, आपदा राहत, एम्बुलेंस और रक्त बैंक सेवा *मैगन डेविड एडोम* (एमडीए) ने बताया कि मध्य इजराइल में ईरान केबैलिस्टिक मिसाइल हमले में दो लोगों की मौत हो गई।

राजनीति में फुल स्टॉप नहीं ...

किया है और उनका अनुभव लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की सराहना करते हुए उन्हें मृदुभाषी और कुशल संचालक बताया। उन्होंने कहा कि सदन को सुचारु रूप से चलाने में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हरिवंश सदन के बाहर भी युवाओं के बीच सक्रिय रहते हैं और उन्हें देश की परिस्थितियों से अवगत कराने का कार्य करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रामदास अठावले के हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक अंदाज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में 24×7 मीडिया के कारण सदन में हास्य-विनोद के अवसर कम हो गए हैं, लेकिन अठावले अपने अंदाज से वातावरण को सहज बनाए रखते हैं और लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री ने संसदीय प्रणाली में *सेकंड ओपिनियन* की अवधारणा को लोकतंत्र की बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि एक सदन में लिए गए निर्णय दूसरे सदन में विचार के लिए जाते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया और अधिक समृद्ध और व्यापक बनती है।

दुबई समेत पूरे यूएई ...

करने की सलाह दी गई है। बुधवार को इस बारे में दुबई और शारजाह समेत पूरे यूएई में मस्जिदों और लोकल अथॉरिटी ने ऐलान शुरू कर दिया है। अथॉरिटी ने कहा कि यह कदम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। अथॉरिटी अधिकारियों ने नमाजियों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करें और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के लिए समय से पहले पहुंचें। साथ ही कहा कि ईदगाह और मस्जिदों से बाहर नमाज पढ़ने से बचें। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक सड़कों या खुले स्थानों पर नमाज पढ़ने से रोकने के लिए नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं, और उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए यूएई ने ये फैसला लिया है। यूएई की चांद देखने वाली समिति बुधवार यानी आज 29वें रोजे पर चांद देखेगी। 18 मार्च को आसमान में शव्वाल के चांद को देखने की कोशिश की जाएगी। अगर चांद दिखाई दे जाता है तो ईद-उल-फितर का त्योहार गुरुवार यानी 19 मार्च को मनाया जाएगा। अगर चांद दिखाई नहीं देता है तो रमजान के पूरे 30 रोजे होंगे और ई शुक्रवार (20 मार्च) को होगी। अगर खाड़ी देशों में 18 मार्च को शव्वाल का चांद दिख जाता है तो वहां 19 मार्च को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में भारत में भी 20 मार्च को ईद मनाई जा सकती है। दरअसल, खाड़ी देशों के एक दिन बाद भारत में अक्सर ईद का त्योहार मनाया जाता रहा है। अगर खाड़ी देशों में 20 मार्च को ईद होगी तो भारत में ये त्योहार 21 मार्च को मनाया जाएगा। वैसे खगोलीय गणनाओं के अनुसार, इस साल रमजान के पूरे 30 दिन चलने की संभावना है।

पालम अग्निकांड : एक ...

में खड़े लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन लपटों की भयावहता के आगे कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस भयावह मंजर के बीच एक पिता का साहसिक कदम सामने आया। राजेंद्र कश्यप के बेटे अनिल ने अपनी एक साल की मिताली बच्ची को बचाने के लिए उन्हें दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। नीचे खड़े लोगों ने किसी बच्ची को संभालने की कोशिश की। इस बीच अनिल भी नीचे कूद गए। उनके सिर में भी गंभीर चोट आई है। चश्मदीदों के मुताबिक एक व्यक्ति दमकल विभाग की सीढ़ी के जरिए नीचे उतर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। इस घटना ने बचाव कार्य की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह इमारत मार्केट के प्रधान राजेंद्र कश्यप की थी और इसका ढांचा किसी *डेथ ट्रैप* से कम नहीं था। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर, चूड़ी और कॉस्मेटिक का बड़ा शोरूम था, जहां भारी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री रखी गई थी। इसके अलावा कपड़ो का भी काम था। इसी कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। वहीं ऊपरी मंजिलों पर परिवार के करीब 15 सदस्य रहते थे।

राज्य सरकार ने विकास के नए कीर्तिमानों का एक नया दौर लिखा : असम भाजपा

गुवाहाटी (हिंस)। आगामी असम विधानसभा चुनाव 2026 में असम की जनता नि:स्संदेह कांग्रेस के 60 वर्षों के शासन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तहत विकास के मात्र 10 वर्षों के बीच तुलना करेगी। असम की जनता के समग्र कल्याण और व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के मामले में, भाजपा शासन का पिछला दशक इतिहास में वास्तव में उल्लेखनीय रूप से दर्ज होगा। इन 10 वर्षों में, सरकार ने लोगों की कल्पना से कहीं अधिक विकास कार्य किए हैं। असम में कभी यह धारणा व्यापक रूप से प्रचलित थी कि *आंदोलन के बिना असम को कुछ नहीं मिलता, और केंद्र असम के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करता है।* हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राजग सरकार ने पिछले 12 वर्षों में, विकास के लिए असम को रिकॉर्ड तोड़ वित्तीय सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों ने अक्सर असम का दौरा किया है, और हर बार नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिससे राज्य में विकास का नक्शा ही बदल गया है। ये टिप्पणियां प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कमल कुमार मेधी ने बुधवार को असम प्रदेश भाजपा मुख्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कीं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि एक समय था जब असम के राष्ट्रीय राजमार्गों को मीडिया द्वारा कुख्यात रूप से *मौत के जाल* के रूप में वर्णित किया जाता था। आज, भाजपा शासन के तहत, यही राजमार्ग विमानों की आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने में सक्षम हैं। पिछले 10 वर्षों में, कुल 65 हजार किमी सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे पूरे राज्य में कनेक्टिविटी काफी मजबूत हुई है। पिछले पांच वर्षों में, असम में 1,330 पुलों का निर्माण किया गया है। 13 मार्च को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलचर में एक हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी, जिसमें ?22,864 करोड़ का निवेश शामिल है, जिससे पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत हुई है। भाजपा शासन के दौरान, ब्रह्मपुत्र नदी पर नौ पुल पहले ही पूरे हो चुके हैं। काजीरंगा में 6,950 करोड़ के निवेश से एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया है। रिंग रोड और गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ने वाली सुरंग जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्टर परियोजनाएं, जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, अब इस सरकार के तहत हकीकत बन रही हैं। पिछले एक दशक में, असम के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने 15 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पूरा कर लिया है और राज्य में एम्स जैसे प्रमुख संस्थान स्थापित किए गए हैं। हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2,092 करोड़ की कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा, 16,500 बच्चों की सफल हार्ट सर्जरी ने पूरे असम में अनगिनत परिवारों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बाढ़ की पुरानी समस्या को हल करने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले पांच वर्षों में, 2,000 किमी से अधिक लंबे तटबंध बनाए गए हैं। पिछले साल की बाढ़ के दौरान, राज्य भर में केवल तीन जगहों पर तटबंध टूटे; यह पहले के समय से बिल्कुल अलग है, जब हर साल अलग-अलग जिलों में तटबंध टूट जाते थे, जिससे बार-बार उनकी मरम्मत करनी पड़ती थी। अन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मेधी ने कहा कि *मिशन बसुंधरा* के तहत, असम के 4,50,000 मूल निवासी परिवारों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। 200 से अधिक वर्षों से चली आ रही एक कमी को खत्म करते हुए, भाजपा सरकार ने चाय बागान श्रमिकों को सफलतापूर्वक जमीन के अधिकार दिए हैं, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अपना विश्वास दोहराते हुए, मेधी ने जोर देकर कहा कि विकास की इन अभूतपूर्व उपलब्धियों को देखते हुए, असम की जनता एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार को सत्ता में वापस लाएगी।

मणिपुर के प्रतिबंधित संगठनों के तीन कैडर गिरफ्तार

इंफाल (हिंस)। मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के विरुद्ध जारी अभियान की कड़ी में बीते 24 घंटों के दौरान पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों से तीन उग्रवादी संगठनों के तीन कैडरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई तरह की सामग्री भी बरामद की गयी है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा आज सुबह जारी बयान में बताया गया है कि मंगलवार को सुरक्षा बलों ने काकचिंग जिले के सुगनू थानांतर्गत सिंगटॉम इलाके से प्रतिबंधित संगठन आरपीएफ/पीएलए के एक सक्रिय कैडर एलांगबम अबिनाश उर्फ राकेश (21) को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से काकचिंग जिला के हियांगलाम माखा लेइकाई का रहने वाला बताया गया है। दूसरे अन्य एक अभियान में इसी दिन सुरक्षा बलों ने इंफाल पूर्वी जिले के इरिलबुंग थानांतर्गत इरिलबुंग हाई स्कूल, बामोन कांपू के पास से प्रतिबंधित संगठन केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के एक सक्रिय कैडर इंफाल पूर्वी जिले के वांगखेई अयांगपल्ली निवासी मुतुम रंजन सिंह उर्फ मंगल (46) को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक स्कूटर जब्त किया गया। तीसरे अभियान में सुरक्षा बलों ने इंफाल पश्चिमी जिले के सिंगजामेई थानांतर्गत कांचीपुर इलाके से प्रतिबंधित संगठन प्रीपाक (प्रो) के एक सक्रिय कैडर इंफाल पूर्वी जिले के चानम सांड्रोक माखा लेइकाई निवासी ताओरेम अरुणकुमार सिंह (32) को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड जब्त किया गया। इस बीच राज्य के संवेदनशील जिलों के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल तलाशी अभियान और क्षेत्र पर नियंत्रण जारी रखे हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि मंगलवार को चलाए गये अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर जरूरी सामान ले जाने वाले 326 वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वाहनों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा काफिला उपलब्ध कराया गया है। मणिपुर के अलग-अलग जिलों में, पहाड़ों और घाटियों दोनों में इस दौरान कुल 114 नाके एवं चेक पॉइंट लगाए गए थे, हालांकि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया।

राज्य में पीएनजी कनेक्शन विस्तार की पहल, एलपीजी पर निर्भरता घटाने की तैयारी

गुवाहाटी (हिंस)। लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आपूर्ति की बदलती स्थिति और उससे जुड़े भू-राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन के विस्तार को लेकर समीक्षा की है और राज्य में इसके विस्तार की प्रक्रिया शुरू की है। इसकी जानकारी आज राज्य सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से जारी एक बयान में कह गयाा है कि यह समीक्षा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के लोगों को विश्वसनीय और सुविधाजनक ऊर्जा उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि पीएनजी का विस्तार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और एलपीजी पर निर्भरता को कम करेगा। राज्य में पीएनजी अवसंरचना विकसित करने का कार्य असम गैस कंपनी लिमिटेड (एजीसीएल), पूर्व भारतीय गैस प्राइवेट लिमिटेड (पीबीजीपीएल) और नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनईजीडीसीएल) को सौंपा गया है, जो चयनित जिलों में पाइपलाइन नेटवर्क तैयार कर रही हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पीएनजी कनेक्शन केवल उन्हीं क्षेत्रों में दिए जाएंगे जहां पाइपलाइन अवसंरचना उपलब्ध होगी। अवसंरचना विस्तार का कार्य जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना है, जिससे पारंपरिक एलपीजी पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सके।

एनटीपीसी बंगाईगांव ने राष्ट्र निर्माण के प्रति जताई अपनी प्रतिबद्धता

कोकराझाड़ (हिंस)। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) बंगाईगांव ने स्टेशन पर आयोजित अपने वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लगातार बेहतर परिचालन प्रदर्शन, टिकाऊ प्रथाओं और प्रभावशाली सामुदायिक पहलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्टेशन परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान एनटीपीसी बंगाईगांव के परियोजना प्रमुख अर्नब मैत्रा ने बताया कि परिचालन उत्कृष्टता, पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्र में सार्थक सामुदायिक विकास पहलों पर संतुलित ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी कार्यों में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। 750 मेगावाट (3म250 मेगावाट) की स्थापित क्षमता के साथ, एनटीपीसी बंगाईगांव असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, स्टेशन ने अब तक लगभग 4110 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन किया है, जिससे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है और ग्रिड स्थिरता में योगदान मिला है। उन्होंने आगे बताया कि एनटीपीसी बंगाईगांव में स्थापना के बाद से 13 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 50,000 से

अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिससे परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास हरित आवरण और पारिस्थितिक संतुलन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि परिचालनात्मक प्रदर्शन एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना रहा, जिसमें स्टेशन ने 93.72 प्रतिशत की घोषित क्षमता हासिल की, जो संयंत्र की बेहतर उपलब्धता और रखरखाव प्रक्रियाओं को दर्शाती है। संयंत्र का लोड फैक्टर लगभग 65.43 प्रतिशत रहा, जो ग्रिड की मांग और प्रेषण अनुसूची के अनुरूप है। वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यूनिट-1 का 433 दिनों तक निरंतर संचालन रहा, जो मजबूत परिचालन अनुशासन और उपकरण विश्वसनीयता को दर्शाता है। संसाधन अनुकूलन के क्षेत्र में, स्टेशन ने 2.50 लीटर/किलोवाट घंटा की सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट जल खपत दर्ज की। एनटीपीसी बंगाईगांव ने स्थापना के बाद से उच्चतम स्तर पर 170 प्रतिशत से अधिक राख उपयोग हासिल किया, जिसमें 14,737.83 मीट्रिक टन का रिकॉर्ड एकल-दिवसीय उपयोग और महत्वपूर्ण मासिक उपयोग स्तर शामिल हैं, जो कुशल राख प्रबंधन, टिकाऊ अपशिष्ट उपयोग और अवसंरचना विकास में योगदान करते हैं। परिचालन के अलावा, एनटीपीसी बंगाईगांव ने पूर्वोत्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, अवसंरचना, खेल और सांस्कृतिक संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सीएसआर पहलों को मजबूत करना जारी रखा है। इन पहलों से 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है, जबकि बीटीआर में 2 लाख से अधिक और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 10 लाख लोगों को लाभ हुआ है। मैत्रा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, डिजिटल साक्षरता केंद्र और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों और स्मार्ट कक्षाओं का विकास शामिल है। लखपति बैदेउ कार्यक्रम, एरी रेशम और हथकरघा को बढ़ावा देने और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसी कौशल विकास पहलों ने आजीविका सृजन और महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया है। इस स्टेशन ने ग्रामीण खेल अवसंरचना के विकास, फुटबॉल और क्षेत्रीय टूर्नामेंटों को समर्थन देने, डूरंड कप, संसद खेल महोत्सव जैसे आयोजनों से जुड़ने और महिला एवं उभरते खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण खेल पहलों का आयोजन करके खेलों और युवा भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। मैत्रा ने बताया

राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु *भारती बहुभाषी अनुवाद सारथी* प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

बंगाईगांव (हिंस)। राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु *भारती बहुभाषी अनुवाद सारथी* प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी के तत्वावधान में तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगाईगांव रिफाइनरी के सहयोग से बंगाईगांव रिफाइनरी के आरसीसीसी सभागार में *भारती बहुभाषी अनुवाद सारथी* विषय पर पूर्वोत्तर के कार्यालयों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंशुली आर्य, भप्रसे, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए तकनीक आधारित अनुवाद प्रणालियां प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुलभ, प्रभावी एवं समावेशी बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने *भारती बहुभाषी अनुवाद सारथी* को राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इस अवसर पर एन के बरुवा, कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख सह अध्यक्ष, नराकास, बंगाईगांव ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से भाषा संबंधी कार्यों में दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को उनके कार्यक्षेत्र में राजभाषा के प्रभावी उपयोग हेतु सक्षम बनाएगा। कार्यक्रम में राजीव कुमार नायक, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गुवाहाटी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र सी-डेक, पुणे से शशिपाल सिंह एवं उनकी टीम द्वारा संचालित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को *भारती बहुभाषी अनुवाद सारथी* मंच की कार्यप्रणाली, उपयोगिता एवं व्यवहारिक अनुप्रयोगों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में कर्फ्यू 20 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, दिन के समय छूट दी गई

तुरा। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिला प्रशासन ने बुधवार को मौजूदा कर्फ्यू को 20 मार्च तक, यानी 24 घंटे और बढ़ा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट विभोर अग्रवाल ने घोषणा की कि यह कदम स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद उठाया गया है ताकि सामान्य स्थिति बहाल की जा सके और हिंसा को और बढ़ने से रोका जा सके। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि कर्फ्यू 19 मार्च को सुबह 6 बजे से 20 मार्च को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले ही वापस नहीं ले लिया जाता। एक आदेश में कहा गया, मैं, श्री विभोर अग्रवाल, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम गारो हिल्स जिला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम गारो हिल्स जिले के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में लागू कर्फ्यू को एक और अवधि के लिए बढ़ाता हूं। तदनुसार, कर्फ्यू 19 मार्च 2026 की सुबह 6 बजे से 20 मार्च 2026 की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले ही हटा न लिया जाए। कर्फ्यू की अवधि के दौरान, पश्चिम गारो हिल्स जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति अपने निवास से बाहर नहीं निकलेगा, आदेश में आगे कहा गया है। हालांकि, जन आवागमन और नियमित गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए 19 मार्च को पूरे जिले में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक समय में छूट दी जाएगी। आदेश में कहा गया है, पश्चिम गारो हिल्स जिले के सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। आज सुबह मेघालय सरकार ने हालिया हिंसा के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के संकेत मिलने के बाद गारो हिल्स क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दीं। अशांति के कारण दो लोगों की मौत हो जाने और व्यापक व्यवधान उत्पन्न होने, विशेष रूप से तुरा में, के बाद एहतियात के तौर पर पांच जिलों-पश्चिम गारो हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, दक्षिणी गारो हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स और दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स-में संपर्क निलंबित कर दिया गया था।

देबब्रत सैकिया ने जुबीन गर्ग मौत मामले की निगरानी के लिए नागरिक निगरानी समिति का प्रस्ताव रखा

गुवाहाटी। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और नाजिरा के विधायक देबब्रता सैकिया ने असम की जनता से एकजुट होकर एक नागरिक न्याय निगरानी समिति गठित करने का आह्वान किया है ताकि सांस्कृतिक हस्ती जुबीन गर्ग को न्याय मिल सके। सैकिया ने सुझाव दिया है कि समिति का गठन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कानून के प्रोफेसरों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को मिलाकर किया जाए। जांच की गति और पारदर्शिता पर चिंता जताते हुए, विपक्ष के नेता ने कहा कि जुबीन गर्ग की दुखद मौत को छह महीने बीत चुके हैं, फिर भी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जनता के संदेह बने हुए हैं। असम सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी)

द्वारा दायर आरोपपत्र में खामियों के कारण अदालत के आदेश के बाद जुबीन हत्याकांड के मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत का बैंक खाता अनफ्रीज कर दिया गया है। नतीजतन, असम का नागरिक समाज चिंतित है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रभाव हो सकता है क्योंकि जुबीन भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते थे, सैकिया ने कहा। उनके अनुसार, प्रस्तावित पैनल अनुभवी पर्यवेक्षकों के माध्यम से कानूनी कार्रवाई के हर चरण पर नजर रखेगा, विस्तृत रिकॉर्ड रखेगा और जनता की समझ के लिए जटिल कानूनी घटनाक्रमों को सरल बनाएगा। यह पैनल आरोप पत्र, अदालती फैसलों और मामले के प्रक्रियात्मक पहलुओं की भी जांच करेगा। इसके अलावा, समिति दिवंगत कलाकार के परिवार और उनके वकीलों को आवश्यक कानूनी शोध और सूचनात्मक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, यदि अभियोजन पक्ष के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो समिति वकील और जुबीन के परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह समिति मामले से संबंधित सभी सार्वजनिक दस्तावेजों, निर्देशों और समय-सारणी का एक डिजिटल भंडार बनाएगी। हालांकि यह अदालती कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करेगी, समिति न्यायिक प्रणाली का सम्मान करते हुए कार्य करेगी और जनता को नियमित रूप से जानकारी देकर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

श्रीभूमि में करंट लगने से बिजली विभाग के कर्मी की मृत्यु

श्रीभूमि (हिंस)। श्रीभूमि जिला शहर में बिजली के खंभे पर काम करते समय अचानक लक्ष्मण चक्रवर्ती नामक विभागीय कर्मी की बिजली के संपर्क में आने से उसकी मृत्यु हो गई। हादसे के बाद बिजली कर्मी को तुरंत श्रीभूमि सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को मृतक के परिजनों ने बताया है कि जब तक विभागीय अधिकारी मौके पर नहीं आते हैं तब वे शव को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं करिमगंज सदर अस्पताल में किसने मृतक के शव को पहुंचा था, इस बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर पहुंची श्रीभूमि पुलिस द्वारा जांच जारी है।

नगांव जिले में वोटिंग मशीनों का रैंडमाइजेशन संपन्न

नगांव (निसं)। असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत आज जिला आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के अंतर्गत सात विधानसभा क्षेत्रों-55 नं. धिंग, 56 नं. रुपहीहाट, 57 नं. कलियाबोर, 58 नं. सामगुड़ी, 59 नं. बड़हमपुर, 60 नं. नगांव-बटद्रवा और 61 नं. रहा (अनुसूचित जाति)-के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के प्रथम चरण का रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने की। यह प्रक्रिया जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष मौजूदगी में कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से संपन्न की गई।

भारतीय सेना और राष्ट्रीय रक्षा बल ने रक्षा रसद को मजबूत करने के लिए संयुक्त रणनीति बनाई

गुवाहाटी। भारतीय सेना और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को गुवाहाटी में पूर्वी क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने और परिचालन तत्परता में सुधार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य संयुक्त प्रतिक्रिया तंत्र को सुव्यवस्थित करके आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों को बढ़ाना था। इस बैठक में सेना की पूर्वी कमान और एनएफआर के अधिकारियों ने क्षमताओं का आकलन करने और संसाधनों को अनुकूलित करने के तरीकों का पता लगाने के लिए भाग लिया। इस अभ्यास में परिदृश्य-आधारित योजना शामिल थी जिसका उद्देश्य संभावित आकस्मिकताओं की पहचान करना और संकट के दौरान त्वरित, समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। अधिकारियों ने अधिक एकीकृत और कुशल प्रणाली के निर्माण के लिए दोनों संगठनों की ताकत का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया। एक प्रमुख फोकस क्षेत्र दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का विकास था जो नागरिक और सैन्य दोनों जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसी पहलों से रसद व्यवस्था में सुधार होने के साथ-साथ कुल खर्च में कमी आने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सेना और रेलवे के बीच घनिष्ठ सहयोग से गंभीर परिस्थितियों के दौरान निर्बाध समन्वय संभव हो सकेगा, जिससे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी क्षेत्र में परिचालन संबंधी चुनौतियों के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।

रसोई गैस की समस्या : नगांव प्रशासन ने फोन के जरिए शिकायत दर्ज कराने की दी सुविधा

नगांव (निसं)। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न भू-राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नगांव जिला प्रशासन ने सक्रिय कदम उठाए हैं। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, इस विषय से संबंधित किसी भी शिकायत को फोन के माध्यम से दर्ज कराने हेतु नगांव जिला प्रशासन की ओर से एक टोल-फ्री नंबर जारी किया गया है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 1077 नंबर पर नगांव जिले के लोग एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नगांव जिले के उपायुक्त देवाशीष शर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने रसोई गैस के अवैध उपयोग और जमाखोरी के खिलाफ भी अभियान शुरू कर दिया है।

कोकराझाड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका

जिला सांगठनिक संपादक बहारुल इस्लाम बीपीएफ में शामिल

कोकराझाड़ (विभास)। कोकराझाड़ जिले में कांग्रेस पार्टी को उस समय एक बड़ा झटका लगा, जब जिला कांग्रेस कमेटी के सांगठनिक संपादक बहारुल इस्लाम ने पार्टी का साथ छोड़कर बोड़ोलैंड पीपुल्स फ्रंट का दामन थाम लिया। बुधवार को कोकराझाड़ जिले के फकीराग्राम में आयोजित बीपीएफ की एक महत्वपूर्ण सभा के दौरान बहारुल इस्लाम आधिकारिक रूप से दल में शामिल हुए। बीपीएफ के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बहारुल इस्लाम कोकराझाड़ जिला कांग्रेस के सांगठनिक संपादक के रूप में कार्यरत थे। बीपीएफ की सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम फकीराग्राम में आयोजित

किया गया। चुनाव से पहले कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सांगठनिक पदाधिकारी का बीपीएफ में जाना जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए बीपीएफ नेताओं ने बहारुल इस्लाम का स्वागत किया और कहा कि उनके आने से क्षेत्र में पार्टी का सांगठनिक ढांचा और अधिक मजबूत होगा।

संपादकीय

चुनावी दुराग्रह के तबादले

चुनाव होने हैं, शीर्ष अधिकारियों की अग्नि-परीक्षा नहीं होनी है। अधिकारी भाजपाई या तृणमूल के बंधक नहीं होते। वे कानून और संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं। कोई अपवाद हो सकता है कि 'काली भेड़' साबित हो। उसे दंडित किया जा सकता है। उसका तबादला किसी 'काले पानी' की तरफ किया जा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस के तबादले किए गए हैं, वे न तो न्यायसंगत हैं और न ही निरपेक्ष हैं। चुनाव आयोग ने अपराह्न 4 बजे चुनावों की तारीखें घोषित की हैं और गहरी रात, अर्थात् आधी रात, में बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था के प्रमुख, कोलकाता के पुलिस आयुक्त आदि के एक साथ तबादले कर दिए गए। हम मानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को व्यापक शक्तियां देता है, लेकिन ये तबादले राजनीतिक मंशा और दुराग्रह से किए गए हैं। यह भी सर्वोच्च अदालत का फैसला है कि ऐसे शीर्ष अधिकारियों के तबादले दो साल से पहले नहीं किए जा सकते। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में वरिष्ठतम होते हैं और संघ लोक सेवा आयोग इनकी अनुशंसा करता है। कोई राजनीतिक बॉस इनका नियोक्ता नहीं है। सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग को कैसे पता कि ये अधिकारी निष्पक्ष चुनाव और हिंसामुक्त माहौल में चुनाव नहीं करा सकते अथवा ये सभी अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वफादार हैं? आयोग ने एक ही झटके में बंगाल की शीर्ष नौकरशाही को हिला कर रख दिया। क्या रोजमर्रा का प्रशासन चुनाव आयोग चलाएगा? यदि बंगाल में प्रशासनिक बदलाव किया गया है, तो तमिलनाडु और केरलम में ऐसा क्यों नहीं किया गया? असम में दिखावे को पांच जिलों के एसएसपी बदले गए हैं। संदेह होता है कि चुनाव आयोग किसी की 'कठपुतली' बनकर काम कर रहा है। भारत के लिए यह विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारा चुनाव आयोग वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण रहा है और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हमारे चुनावों के दौरान 'पर्यवेक्षक' की भूमिका में होते हैं। बेशक बंगाल में राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। पहले वामपंथी गांव-गांव, कस्बा-दर-शहर हत्याएं कराते थे। अब 2011 से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक काडर हत्याएं कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक मंच से इन राजनीतिक हिंसाओं का उल्लेख कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में 7 ऐसी हत्याएं की गईं और 740 लोग घायल हुए। उनमें से जिंदा बचने वालों का कोई अधिकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। घर तक जला दिए गए। हत्या के बाद शवों को पेड़ से लटकाया जाता रहा। केरलम में तो हिंसा का ऐसा बर्बर रूप है कि विरोधी पक्ष के सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं की टांगें तक तोड़ कर उन्हें अपाहिज बना दिया जाता है। कोई भी नौकरशाह इस राजनीतिक हिंसा को रोक नहीं सकता। चुनाव आयोग मुगालते में होगा! तमिलनाडु में भी द्रविड़ बनाम हिंदू और गैर-द्रविड़ के दरमियान उग्रता, क्रूरता के कई उदाहरण सामने आते रहे हैं। उन राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सरीखे शीर्षतम नौकरशाही को क्यों नहीं बदला गया? सिर्फ इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव, 2024 से पहले गुजरात, उप्र, बिहार, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों में सिर्फ गृह सचिव बदले गए थे। हिमाचल और झारखंड को छोड़ कर शेष राज्यों में भाजपा-एनडीए सरकार थी और आज भी है। जब महाराष्ट्र, हरियाणा, उप्र, मप्र आदि में विधानसभा चुनाव थे और विपक्षी कांग्रेस ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को बदलने की मांग की थी, तो चुनाव आयोग ने नकार कर दिया था? इन राज्यों में भी भाजपा-एनडीए सरकारें थीं और आज भी हैं। साफ लग रहा है कि चुनाव आयोग का व्यवहार पक्षपातपूर्ण रहा है। दरअसल संवैधानिक संस्था के मायने ये नहीं हैं कि आयोग निरंकुशता और स्वच्छंदता से काम करे, फैसले ले।

> चुनाव आयोग ने अपराह्न 4 बजे चुनावों की तारीखें घोषित की हैं और गहरी रात, अर्थात आधी रात, में बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था के प्रमुख, कोलकाता के पुलिस आयुक्त आदि के एक साथ तबादले कर दिए गए। हम मानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को व्यापक शक्तियां देता है, लेकिन ये तबादले राजनीतिक मंशा और दुराग्रह से किए गए हैं। यह भी सर्वोच्च अदालत का फैसला है कि ऐसे शीर्ष अधिकारियों के तबादले दो साल से पहले नहीं किए जा सकते। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में वरिष्ठतम होते हैं और संघ लोक सेवा आयोग इनकी अनुशंसा करता है। कोई राजनीतिक बॉस इनका नियोक्ता नहीं है। सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग को कैसे पता कि ये अधिकारी निष्पक्ष चुनाव और हिंसामुक्त माहौल में चुनाव नहीं करा सकते अथवा ये सभी अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वफादार हैं? आयोग ने एक ही झटके में बंगाल की शीर्ष नौकरशाही को हिला कर रख दिया। क्या रोजमर्रा का प्रशासन चुनाव आयोग चलाएगा? यदि बंगाल में प्रशासनिक बदलाव किया गया है, तो तमिलनाडु और केरलम में ऐसा क्यों नहीं किया गया? असम में दिखावे को पांच जिलों के एसएसपी बदले गए हैं। संदेह होता है कि चुनाव आयोग किसी की 'कठपुतली' बनकर काम कर रहा है।

कुछ अलग

राजा ने भिखारी से मांगा अनाज

पुराने समय में एक छोटे से राज्य के राजा प्रजा के हाल जानने के लिए समय-समय पर घूमता था। एक दिन राजा घूमते-घूमते एक भिखारी के पास पहुंचा। उसने भिखारी से कहा, "भैया, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। मेरे गुरु ने कहा है कि इससे मेरे राज्य का संकट दूर होगा।" भिखारी हैरान रह गया। उसने सोचा, "एक राजा मुझसे भीख मांग रहा है। मैं मना कैसे करूं?" उसने अपनी झोली में हाथ डाला और मुट्ठी भर अनाज राजा को देने लगा, लेकिन मन ही मन वह सोचने लगा, "इतना अनाज राजा को दूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। ज्यादा नहीं देना चाहिए।" इसलिए उसने अपनी मुट्ठी से कुछ अनाज झोली में ही छोड़ दिया और सिर्फ थोड़ा सा राजा को दे दिया। राजा ने अनाज लेकर अपने मंत्री को दिया और कहा, "इस अनाज के बराबर का इनाम भिखारी को देना।" मंत्री ने भिखारी के लिए एक पोटली तैयार की और उसे दे दी। भिखारी जब घर आया, तो उसने पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी ने पोटली खोली और देखा कि उसमें सोने के सिक्के हैं। भिखारी और उसकी पत्नी दोनों बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ में आया कि अगर उन्होंने राजा को पूरा अनाज दिया होता, तो उन्हें और ज्यादा सोना मिलता। भिखारी को पछतावा हुआ कि उसने कंजूसी की। दोनों पति-पत्नी को समझ आ गया कि दान करते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जरूरतमंद को खुश होकर देना चाहिए। छोटे दान में भी खुशी हो, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। जब हम किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं, तो खुश होकर दें। मन में कोई उम्मीद या अहंकार न रखें। खुशी से दिया गया दान सबसे ज्यादा फल देता है।

अमेरिकी-इजरायली कार्रवाई के बाद एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और औचित्य दोनों पर सवाल उठा है

वैश्विक दबंगई देखने को लाचार संयुक्त राष्ट्र

उमेश चतुर्वेदी

> संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का सबसे बड़ा कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित लीग ऑफ नेशन्स की असफलता रही। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की पहल पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को स्थापित लीग ऑफ नेशन्स पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसका मुख्य उद्देश्य कूटनीति और सामूहिक सुरक्षा के जरिए विश्व शांति बनाए रखना था। लीग ऑफ नेशन्स का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रों के बीच के विवादों को सुलझाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर निरस्त्रीकरण को अमली-जामा पहनाना रहा। लेकिन जिनेवा में स्थित वह संस्था ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रही। उसकी नाकामी के चलते जर्मनी और जापान ने विस्तारवादी नीतियां ना सिर्फ अपनाईं, बल्कि रोजाना नए-नए राष्ट्रों पर कब्जा और हमला करने लगे।

ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इजरायली कार्रवाई के बाद एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और औचित्य दोनों पर सवाल उठा है। दिलचस्प यह है कि अमेरिका ने अतीत में जब भी ऐसी कार्रवाई की, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को लागू करने का बहाना बनाया। चूंकि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप अलबेले राजनेता हैं, उनके लिए नियम-कायदों और जगतगति से ज्यादा उनकी अपनी जुबान और सोच मायने रखता है। इसलिए ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओट लेने की औपचारिकता भी नहीं निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का सबसे बड़ा कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित लीग ऑफ नेशन्स की असफलता रही। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की पहल पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को स्थापित लीग ऑफ नेशन्स पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसका मुख्य उद्देश्य कूटनीति और सामूहिक सुरक्षा के जरिए विश्व शांति बनाए रखना था। लीग ऑफ नेशन्स का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रों के बीच के विवादों को सुलझाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर निरस्त्रीकरण को अमली-जामा पहनाना रहा। लेकिन जिनेवा में स्थित वह संस्था ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रही। उसकी नाकामी के चलते जर्मनी और जापान ने विस्तारवादी नीतियां ना सिर्फ अपनाईं, बल्कि रोजाना नए-नए राष्ट्रों पर कब्जा और हमला करने लगे। इसके बाद जो हुआ, वह विश्व इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। बेशक लीग ऑफ नेशन्स को 20 अप्रैल 1946 को आधिकारिक रूप से भंग किया गया, लेकिन इसके पहले ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। इसकी स्थापना के लिए बड़ा आधार जापान पर हुए अमेरिकी अणुबम हमले के बाद उपजी मानवीय त्रासदी रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना और

विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह अपने इस प्राथमिक उद्देश्य में सफल है? इस पर चर्चा से पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर ध्यान देना जरूरी है, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य, दुनिया भर में शांति बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। इसके साथ ही उसका एक और मकसद, राष्ट्रों के बीच समानता और आत्म-निर्णय के सिद्धांतों के आधार पर दोस्ताना संबंधों का विकास करना भी रहा है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में साफ लिखा है कि यह अंतरराष्ट्रीय संगठन बिना किसी जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के पूरी दुनिया के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। उसका मकसद, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग स्थापित करने के साथ ही, गरीबी दूर करने, भूख, बीमारी और निरक्षरता से लड़ने और प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता प्रदान करने का भी रहा है। इसके साथ ही उसकी भूमिका अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए प्रयास करने की भी है। कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका ऐसे समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करने की सोची गई, जिसके मंच पर विश्व के सभी राष्ट्र उसके साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मिलकर काम कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा कर सका है? निश्चित तौर पर इसका जवाब ना में है। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र की हालत सड़क के किनारे बैठे उस असहाय व्यक्ति जैसी हो गई है, जो सड़क पर जारी मारपीट को असहाय भाव से टुकुर-टुकुर देखते को मजबूर रहता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का सबसे प्रमुख उद्देश्य युद्धों को रोकना है। लेकिन ना तो यह शीत युद्ध को रोक सका, ना ही मौजूदा दौर के संघर्षों को रोक पा रहा है। 1991 के खाड़ी युद्ध के लिए तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज बुश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को ही बहाना बनाया था। 2001 में जार्ज बुश के बेटे जूनियर जार्ज बुश और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी इराक और अफगानिस्तान पर हमले के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की उसकी सेना की ओट ली थी। 1994 का रवांडा का नरसंहार हो या फिर 2011 में दक्षिण सूडान में हुआ गृहयुद्ध, 1995 में सर्ब सेना द्वारा बोस्निया में किया गया नरसंहार हो या फिर 2010 के दौरान हुई कथित अरब क्रांति की आड़ में हुई मध्य एशिया की हिंसा, किसी को भी रोकने में संयुक्त राष्ट्र अभियान सफल नहीं रहे। संयुक्त राष्ट्र का मंच राष्ट्रों के बीच संवाद बढ़ाने और विवादों को सुलझाने के बजाय, उनके बीच गाली-गलौज और आपसी आलोचना का केंद्रभर बनकर रह गया है। अभी संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख और ताकतवर अंग सुरक्षा परिषद है। इसका गठन ही गैरबराबरी को बढ़ावा देने का बड़ा आधार बन गया है। इसमें तीन राष्ट्र ऐसे हैं, जो अक्सर अपने वीटो पॉवर का इस्तेमाल नकारात्मक तरीके से करते हैं। अमेरिका, चीन और रूस की ज्यादातर भूमिका नकारात्मक रही है। रही बात ब्रिटेन और फ्रांस की तो उनकी भूमिका मध्यमार्गी है। हालांकि वे भी महत्वपूर्ण मसलों में सीधे हस्तक्षेप करने की भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा नहीं सकते। इसका ही असर है कि ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने हमला कर रखा है और रूस एवं यूक्रेन के बीच चार साल से युद्ध जारी है। मानवाधिकार के मुद्दों पर भी संयुक्त राष्ट्र प्रभावी नजर नहीं आता। कोविड महामारी के दौरान जिस तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तीसरी दुनिया के कमजोर देशों के साथ पक्षपात पूर्ण भूमिका निभाई, वह भी संयुक्त राष्ट्र की नाकामी प्रतीक है। जब से ट्रंप ने अमेरिका की दोबारा कमान संभाली है, तब से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को और ज्यादा पंगु करने की कोशिश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत संयुक्त राष्ट्र के कई अंगों में अपनी आर्थिक भागीदारी और सहयोग उन्होंने घटाना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के मंचों के जरिए अमेरिकी करदाताओं की बड़ी रकम बेकार के कामों में खर्च हो रही है, जिसका अमेरिका को सीधे फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र की स्थिति और भी ज्यादा निरीह होने वाली है। ऐसे में अगर दुनिया के देश संयुक्त राष्ट्र के औचित्य पर ही सवाल उठाने लगें तो दुनिया को हैरत नहीं होनी चाहिए।

देश | दुनीया से

धुंधीले धुएं के आवरण में उत्तर भारतीय पर्वत

फाल्गुन पूर्णिमा के बीतते ही उत्तर भारत के उत्तराखंड में वैसी ही काली-मटमैली धुंध की प्रतिछाया फैली हुई थी, जैसे प्रदूषण के कारण प्रायः दिल्ली तथा अन्य महानगरों में फैली रहती है। संभवतः जम्मू एवं कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और फिर उत्तराखंड के बाद की पर्वतमालाओं में भी ऐसी ही प्राकृतिक स्थिति परिव्याप्त थी। रात-दिन वायुमंडल में परिव्याप्त इस धुंध ने संवेदनशील मनुष्यों के मन-मस्तिष्क व आत्मा को शुष्क कर दिया। मानव, मानवता से विहीन हो गए। फोन करके दिल्ली, नोएडा तथा अन्य नगरों की जलवायु की जानकारी मांगी, तो पता चला वहां स्पष्ट नीला व्योम दिखाई दे रहा है, पर्याप्त धूप है और फाल्गुन की अनुभूतियां विद्यमान हैं। आश्चर्य हुआ कि बसंत के फाल्गुन और पश्चात चैत्र में पर्वतीय क्षेत्र तो सर्वाधिक सौंदर्यवान होकर बासंती रूपरंग में अवतरित होते हैं, किंतु इस वर्ष ऐसा क्या हो गया कि महानगरों के प्रदूषण के रूप में विद्यमान धुएं का कुरूप-काला आवरण पर्वतों व पर्वतीय लघु नगरों में फैला हुआ था। इस धुएं-धुंध ने संवेदनशील एवं प्रकृतिप्रेमी मनुष्यों को भीतर से तोड़-मरोड़ कर रख दिया। ऐसे मनुष्यों के लिए जीते जी ही दुःखद मृत्यु का परिदृश्य चहुंओर उभर आया था। उन्हें भान ही नहीं रहा कि वे जीवन में उपस्थिति हैं। उन्हें ज्ञात ही नहीं रहा कि उनमें प्राण हैं। वे तो अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान के विरुद्ध आरंभ किए गए युद्ध तथा युद्ध के उपरांत उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट से भी अनभिज्ञ थे। उनके मनोमस्तिष्क पर तो धरती-व्योम पर विष की भांति जमी हुई धुंध अविवेक, अज्ञान, संवेदनहीनता तथा स्मृतिशून्यता के प्रहार कर रही थी। वे असहाय थे। स्मृतिहीन थे। तन-मन के रोगी बने हुए थे। अंततः किसी भी समाधान के लिए निरुपाय थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। वे केवल इतना याद रखने योग्य बचे थे कि उनके प्राण, जीवन तथा अस्तित्व पर धुंध-धुएं के रूप में प्राकृतिक मृत्यु हावी हो रही है। प्रकृति के ऐसे निकृष्टतम रूप के साथ आधुनिक जीवन की विसंगतियां, गतिविधियां तथा असभ्यताएं यथावत थीं। दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन सार्वजनिक राजमार्गों, मार्गों, उपमार्गों का राक्षसी बलात्कार कर रहे थे। वाहनों के चालक निर्दयी मशीनों की भांति सड़कों को रौंद रहे थे। कर्कश, तेज व हृदयाघात देने वाले हॉर्न प्राकृतिक कुरूपता को अधिक बढ़ा रहे थे। घरों के निर्माण कार्य में लगी हुई मशीनें एवं टाइल काटने वाले विद्युत चालित कटर धुंध-धुएं के आवरण को अधिक विषैला बना रहे थे। सुना, पढ़ा व कल्पना आधारित नरक साक्षात घट रहा था। धुंधीले धुएं के आवरण को एक-दूसरे की ओर प्रसारित करती हवा, चारों दिशाओं में चल रही थी। प्रायः पूर्वा व पछुआ हवा ही चला करती थी। किंतु इस बार ऋतु विकृति ने एक नवीन विकृत घटना दिखायी। दक्षिण व उत्तर की दिशाएं भी अपने-अपने हिस्से की हवा चला रही थीं तथा धूल-धुंध-धुएं को एक-दूसरे पर व इधर-उधर ठेल रही थीं। होली के बाद यह दुष्चक्र पूरे नौ-दस दिनों तक चला। अभी दो-तीन दिनों से इस स्थिति में कुछ अनुकूल परिवर्तन हुआ है। अब, जब पछुआ व पूर्वा हवा ही बारी-बारी से कुछ समय तक तीव्र होकर प्रसारित हुईं, तब ही उत्तराखंड सहित संपूर्ण उत्तरी हिमालयी क्षेत्र से धुंध-धुएं का नारकीय आवरण हटा। रविवार को वर्षा भी हो गयी। धुंध से ठहरे हुए व ग्रीष्म ताप में बदलते मौसम में शीत पुनः लौट आई है। प्रति वर्ष, वर्ष के सभी माहों, प्रत्येक माह के पंद्रह-पंद्रह दिनों, पंद्रह दिनों में भी प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन में भी प्रति घड़ी मौसम प्रतिकूल होकर सम्मुख होता है। विश्व में विगत सौ, दो सौ वर्षों से प्रतिवर्ष ऐसा हो रहा है। इस पारिस्थितिकी में प्राकृतिक जीवन, भोजन, वन, वनस्पतियां, पंचतत्त्वों का दैनिक अभ्यास, सभी कुछ मानव के लिए निरंतर अव्यवस्थित हुआ है। इस आधुनिक काल में यह अव्यवस्था भीषणतम हो चुकी है। किन्हीं दो वर्षों का कोई भी एक माह, पंद्रह दिन, प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक घड़ी उत्तरोत्तर प्राकृतिक विकृतियों के साथ पृथक स्वरूप में होती है। प्रति वर्ष की घड़ियां, घटियां, दिन, रात्रि, वार, करण, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारक सभी व्यतीत वर्ष की तुलना में नवीन प्राकृतिक चुनौतियों के रूप में सम्मुख होते हैं। इन पर्यावरणीय स्थितियों-परिस्थितियों में मानव का सामान्य ज्ञान, विवेक, सूझबूझ, पारस्परिक सहायता भावना, संवेदनशीलता, अपनत्व, आत्मचिंतन सभी कुछ तिरोहित है। इस कारण वैश्विक पर्यावरणीय, प्राकृतिक, आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, औद्योगिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्याएं परस्पर इस सीमा तक उलझ चुकी हैं कि उन्हें सुलझाने के सूत्र ही अज्ञात प्रतीत होते हैं। अमेरिका-इजरायल तथा ईरान का युद्ध ऐसी ही एक बड़ी उलझन का परिणाम है। रूस तथा यूक्रेन के मध्य का युद्ध इस दशक का सर्वाधिक दीर्घावधि का युद्ध हो चुका है, जो न्यूनाधिक रूप में अभी भी चल ही रहा है। कोरोना काल के बाद रूस व यूक्रेन, इजरायल व फिलीस्तीन, भारत व पाकिस्तान, अमेरिका व ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान तथा अब अमेरिका-इजरायल व ईरान के मध्य के युद्धों ने विश्व को एक अनिश्चित, असुरक्षित एवं अशांत क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है। सूक्ष्म अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन युद्धों के होने-घटने की पृष्ठभूमि में दो ही प्रमुख कारक हैं। एक, देशों की धार्मिक एकाधिकार स्थापित करने की इच्छा। दो, अर्थव्यवस्था के स्तर पर प्रथम स्थान पर स्थापित होने की स्पद्र्धा। सभी देशों के अधिसंख्य जन प्राकृतिक आधार पर जीवन यापन करना चाहते हैं, किंतु इन देशों के प्रत्यक्ष शासक व गुप्त धार्मिक शासक ऐसा नहीं चाहते। वे धार्मिक एकाधिकार एवं आर्थिक प्रभुत्व के लिए विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को अपनी मंशा के अनुरूप विभिन्न प्रकृति विरोधी प्रयोग करने के लिए उकसा रहे हैं। वैज्ञानिक विगत तीन-चार सौ वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। अभी वर्तमान में तो वे पूर्णतः निरंकुश हो चुके हैं। वे प्रगति व आधुनिकता की आड़ में अपने प्रत्येक प्रयोग को विश्व के लिए वरदान कम तथा अभिशाप अधिक सिद्ध कर रहे हैं। जीवन के इस आधुनिक वातावरण में शासक, गुप्त धार्मिक शासक, वैज्ञानिक, धनिक तथा सामान्य जन, सभी आत्मघाती आधुनिक-यात्रा में बहुत दूर निकल चुके हैं। जीवनपतन की ये यात्रा आधे से अधिक पूरी हो चुकी है। अब इस मार्ग पर वापस लौटना असंभव है। अब तो इस यात्रा के पूर्ण होने पर व अखिल जीवन के विनाश होने के बाद ही शांत थाह होगी। ये आभास निरंतर कठोर सत्य प्रतीत होता है कि अब प्रलय के बाद ही प्राकृतिक नवजीवन की स्थापना हो सकेगी। कोई जागरूक हो अथवा नहीं, किंतु वैज्ञानिकों व आविष्कारकों को तो ये सोचकर होना ही होगा कि उनका विज्ञान, उनके आविष्कार मानव के लिए अभिशाप के वज्र बन रहे हैं। उन्हें ये विचार भी करना होगा कि जब अति हर रूप में हानिकारक होती है, तो भला विज्ञान व आविष्कारों के संदर्भ में ये संतुलित कैसे हो सकती है। प्रकृति की कुरूपता, कठोरता, प्रतिकूलता हो अथवा देशों के मध्य धार्मिक व आर्थिक एकाधिकार की स्पद्र्धा के परिणामस्वरूप उत्पन्न विश्व युद्ध की परिस्थितियां, ये मानव का किसी भी स्तर पर उद्धार नहीं करेंगी।

आप का | नजरीया

खनन पर हो मनन

सत्ताधीशों की इच्छा शक्ति की कमी और प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही से खनन माफिया के हौसल बुलंद हैं। कहीं न कहीं नागरिकों की उदासीनता भी इसके मूल में है। पंजाब के रोपड़ जिले की शिवालिक पहाड़ियों में हो रही तबाही उस भयावह स्थिति को दर्शाती है, जिसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वजह साफ है कि अंधाधुंध खनन से शिवालिक पहाड़ियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को भारी क्षति पहुंच रही है। जो हमें यह भी बताता है कि नीति और प्रवर्तन के बीच खाई में पर्यावरणीय अपराध कैसे और किस तेजी से पनपते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे खुदाई करने वाली भारी मशीनों का खुलेआम प्रयोग अवैध खनन हेतु किया जा रहा है। इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की पूरी पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है। जो हमारे पर्यावरण के लिये एक गंभीर चुनौती है। यह क्षति शिवालिक पहाड़ियों के मूल पारिस्थितिक कार्यों मसलन भूजल पुनर्भरण, मृदा-स्थिरता और जैव-विविधता संरक्षण जैसे जीवन रक्षक लक्ष्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दरअसल, यह शिवालिक पर्वतमाला भू-संरचना की दृष्टि से नयी बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। निर्विवाद रूप से किसी भी स्थान पर होने वाली अनियंत्रित खुदाई से भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है। जिसके चलते वर्षा ऋतु और उसके बाद भूस्खलन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है। वहीं इन क्षेत्रों में गाद जमाव का संकट भी गहरा जाता है। कालांतर इसके चलते जल निकासी के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव देखने में आता है। यह सर्वविदित है कि एक बार इन पहाड़ियों को अवैध रूप से काटकर समतल कर दिया जाता है तो उसके मूल स्वरूप को फिर प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें उस क्षेत्र विशेष का प्राकृतिक संरक्षण कवच हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ऐसे में प्राकृतिक सुरक्षा को नष्ट करने वाला विकास कालांतर आपदा का कारक बन सकता है।

> पंजाब के रोपड़ जिले की शिवालिक पहाड़ियों में हो रही तबाही उस भयावह स्थिति को दर्शाती है, जिसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वजह साफ है कि अंधाधुंध खनन से शिवालिक पहाड़ियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को भारी क्षति पहुंच रही है। जो हमें यह भी बताता है कि नीति और प्रवर्तन के बीच खाई में पर्यावरणीय अपराध कैसे और किस तेजी से पनपते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे खुदाई करने वाली भारी मशीनों का खुलेआम प्रयोग अवैध खनन हेतु किया जा रहा है। इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की पूरी पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है। जो हमारे पर्यावरण के लिये एक गंभीर चुनौती है। यह क्षति शिवालिक पहाड़ियों के मूल पारिस्थितिक कार्यों मसलन भूजल पुनर्भरण, मृदा-स्थिरता और जैव-विविधता संरक्षण जैसे जीवन रक्षक लक्ष्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दरअसल, यह शिवालिक पर्वतमाला भू-संरचना की दृष्टि से नयी बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। निर्विवाद रूप से किसी भी स्थान पर होने वाली अनियंत्रित खुदाई से भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है। जिसके चलते वर्षा ऋतु और उसके बाद भूस्खलन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है।

दरअसल, यह ऐसा प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र होता है जो निचले मैदानी इलाकों को बाढ़ और जल संकट से बचाता है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि इस बाबत जवाबदेह अधिकारियों द्वारा दलील दी जाती रही है कि इस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के आधार पर की जाती रही है। साथ ही यह भी सफाई दी जाती है कि ऐसी स्वीकृतियों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन हकीकत तब उजागर हो जाती है जब स्थानीय लोग रात के समय होने वाले खनन कार्यों, निर्धारित सीमा से अधिक और बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाकों में कटाई होने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में अधिकारियों की तमाम दलीलें खोखली ही साबित होती हैं। दरअसल, सवाल नियम-कानूनों की प्रभावकारिता का नहीं है बल्कि असली दिक्कत प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता की है। जो वस्तु-स्थिति से अवगत होने के बावजूद इन आपराधिक कृत्यों के प्रति आंखें मूंदे रहती हैं। दरअसल, खनन कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को आपराधिक तत्वों व राजनेताओं का संरक्षण भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें दो राय नहीं है कि जब अवैध खनन के खिलाफ जमीनी स्तर पर निगरानी के बजाय महज कागजी कार्रवाई का सहारा लिया जाता है तो अवैध खनन को संबल मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि यह अवैध खनन केवल पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों के आसपास ही हो रहा है। पूरे भारत में, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तमाम क्षेत्रों में अवैध खनन लगातार पर्यावरण से जुड़े कानूनों की सीमाओं का उल्लंघन करता नजर आता है। अकसर खनन के लिये दिए गए परमिटों में अस्पष्टता और स्थानीय स्तर पर कमजोर निगरानी का फायदा उठाया जाता है। वह भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फैसलों में बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि आर्थिक गतिविधियां पारिस्थितिकीय नुकसान की कीमत पर नहीं चलायी जा सकती। फिर भी, जमीनी स्तर पर, प्रवर्तन एजेंसियां या तो शक्तिहीन दिखाई देती हैं या निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति उनमें नजर नहीं आती।

दृष्टि | कोण

आसान नहीं भाजपा की पंजाब में वर्चस्व की राह

गत चौदह मार्च को मोगा में अपनी बहुप्रचारित रैली की शुरुआत करते हुए अमित शाह को पगड़ी पहने और सिखों का लोकप्रिय जयघोष करते देखना एक दिलचस्प नज़ारा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर सिख सभाओं में पगड़ी पहनकर आते हैं। जो कोई भी भाजपा नेताओं को सिखों को लुभाने के वास्ते ऐसे हास्यास्पद सुझाव देता है, उसे पंजाब से जुड़े किसी भी राजनीतिक मामले पर सलाह देने से स्थाई तौर पर रोक देना चाहिए। यह कोई राज़ नहीं है कि भाजपा में फ़ैसले शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं। यहां तक कि मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व की मंज़ूरी ज़रूरी रहती है। जाहिर है, आने वाले विधानसभा चुनावों में चुनाव अकेले लड़ने के पार्टी के फ़ैसले का ऐलान करने से पहले अमित शाह ने सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे स्थानीय पार्टी नेताओं से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया था। जबकि कांग्रेस के ये दोनों पूर्व दिग्गज नेता सार्वजनिक तौर पर शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनावी गठबंधन करने की वकालत कर रहे थे। यह रवनीत सिंह बिट्टू ही थे जिन्होंने ऐसे किसी भी गठबंधन का ज़ोरदार विरोध किया है; ऐसे में अगर कल को उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए, तो कोई हैरत नहीं। स्थानीय लोगों के साथ सार्थक संवाद के अभाव में, गृह मंत्री ने अपने भाषण में पसंदीदा अलगाव के मुद्दों में से एक का सहारा लिया—धर्मांतरण। भाजपा जिस 'बदलाव' का वादा कर रही है, यदि उसमें धर्मांतरण-विरोधी क़ानून भी शामिल है, तो चुनावी लिहाज़ से उसे कोई ख़ास सफलता नहीं मिलेगी। धर्मांतरण कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जो आम पंजाबियों को परेशान कर रहा हो। मामूली आर्थिक फ़ायदों के लिए ईसाई धर्म अपनाने वाले ग़रीब लोगों से समाज या राज्य को कोई ख़तरा नहीं है। सबको अपने साथ लेकर चलने वाला पंजाब, धार्मिक आधार पर समाज में अलगाव से चुनाव जीतने के भाजपा के एजेंडे को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। आम तौर पर पंजाबी लोग अहंकारी नेताओं को सत्ता से बाहर करने के

लिए वोट देते हैं। उनकी कोई पसंदीदा पार्टी शायद ही कभी रही है। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली ज़बरदस्त जीत का श्रेय 'आप' के नेतृत्व से किसी बड़ी उम्मीद के बजाय, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के कुशासन के लिए उन्हें दी गई सज़ा को ज़्यादा जाता है। हो सकता है कि अब वे 'आप' से भी मोहभंग महसूस कर रहे हों, लेकिन वे इतने नाराज़ भी नहीं हैं कि उसे सत्ता से ही बेदख़ल कर दें। सिख राजनीतिक विचारक और लेखक, अजमेर सिंह के अनुसार 'भाजपा ने हरियाणा में जाटों को अलग-थलग करके और गैर-जाटों को एकजुट करके चुनाव जीता था। पंजाब में भी वह यही रणनीति अपना सकती है—सिख जाट वोटों को बांटना और हिंदू, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वोटों को एकजुट करना'। डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख को पद्मश्री से सम्मानित करना और उसके बाद दलित बहुल इलाके में गुरु रविदास को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी का डेरा दौरा, ज़ाहिर तौर पर इसी रणनीति का हिस्सा हैं। पंजाब के कुल वोटों में दलितों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है और जालंधर, कपूरथला, नवांशहर और होशियारपुर—इन चार ज़िलों की 117 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों के नतीजों में वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दलितों के बीच रविदासिया समुदाय एक बड़ा हिस्सा है। भाजपा इसी समुदाय पर दांव लगा रही है। भाजपा की इस चुनावी रणनीति को एक और चीज़ से भी मदद मिल रही है—दोषी डेरा प्रमुख राम रहीम की बार-बार पैरोल पर रिहाई। पंजाब के मालवा इलाके के कुछ हिस्सों में राम रहीम के बहुत सारे अनुयायी हैं और फिलहाल उसका पसंदीदा दल भाजपा है। ब्यास स्थित राधा स्वामी डेरा आमतौर पर राजनीतिक रूप से तटस्थ रहता है। भाजपा की दलितों तक पहुंच बनाने की कोशिश भी शायद ही कामयाब हो जाए, क्योंकि पंजाब में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर बंटे हुए हैं और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हैं।

मुख्यमंत्री ने लांच की तीन बड़ी औद्योगिक नीतियां, निवेशकों को दिया आमंत्रण

जयपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से नई पहचान बना रहा है। उद्योग और निवेश आर्थिक समृद्धि के सबसे बड़े आधार हैं और राज्य सरकार उद्यमियों को बेहतर माहौल देने के लिए लगातार नीतिगत सुधार कर रही है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे प्रदेश में निवेश के अवसरों का लाभ उठाकर *विकसित राजस्थान* के निर्माण में भागीदार बनें। मुख्यमंत्री बुधवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित उद्यमी संवाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान दिवस के अवसर पर इस वर्ष 19 मार्च को प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए तीन महत्वपूर्ण नीतियों राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान

एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन नीतियों से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान भविष्य की तकनीकों व रक्षा विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं से जुड़े 119 करोड़ रुपए के 40 कार्यों का लोकार्पण और 226 करोड़ रुपए के 46 कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण के चेक, स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में *रिप्स 2024* और सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब 14 विभागों की 143 से अधिक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिससे उद्योग स्थापना में समय और लागत दोनों की बचत हो रही है। उन्होंने जानकारी दी कि *राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट* में हुए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से आठ लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर आ चुके हैं। साथ ही होंडा द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का प्रस्ताव बढ़ते निवेश विश्वास का संकेत है। उन्होंने कहा कि बीकानेर, पाली, किशनगढ़ और जोधपुर सहित कई क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क विकसित किए गए हैं, जबकि अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट 2026-27 में औद्योगिक विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जोधपुर-पाली-मारवाड़ क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए की लागत से 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी। साथ ही सभी संभागीय मुख्यालयों पर *प्लग एंड प्ले* सुविधा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने दो वर्षों में 31 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए, जबकि पिछली सरकार के पहले दो वर्षों में यह संख्या 16 थी। इसी अवधि में 2, 453 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए और 11.61 लाख एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में राजस्थान देश के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बना है और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। वहीं उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ जैसे क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे।

असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन पद पर बहाली के लिए आवेदकों की काउंसलिंग की गई

अररिया (हिंस)। डीडीसी सह अध्यक्ष जिला चयन समिति की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजनान्तर्गत असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन पद हेतु प्राप्त आवेदनों के आलोक में चयन प्रक्रिया को लेकर बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवेदकों की काउंसलिंग की गई, जिसमें कुल 89 आवेदनों में 50 अभ्यार्थियों ने भौतिक रूप से उपस्थित होकर भाग लिया। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का गहन जांच किया गया। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से सभी आवेदकों का क्रमवार मूल्यांकन किया गया। इस क्रम में अभ्यर्थियों से उनके कौशल एवं अनुभव से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की गई। बैठक में सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

गैस संकट पर पूर्व सीएम का सरकार पर हमला
बोले, *जमीनी हकीकत दावों से अलग*

जयपुर (हिंस)। राजस्थान में गैस सिलेंडर की उपलब्धता के दावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दावों पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री का यह दावा कि *प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है,* जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश का गृहिणी वर्ग और व्यापारी आज गैस सिलेंडर के लिए भटकने को मजबूर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस संकट का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे उद्योग-धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। उनके अनुसार, राजस्थान के करीब 50 हजार होटल और रेस्टोरेंट ठप होने की कगार पर हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी के कारण हलवाई, ढाबा संचालक और छोटे व्यवसायी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रभावित होने से मजदूरों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है, जबकि सरकार निवेश को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है। गहलोत ने अपने बयान में तंज कसते हुए कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी भोजन लकड़ी के चूल्हों पर बनाना पड़ रहा है। उन्होंने इसे सरकार के दावों और वास्तविकता के बीच अंतर का उदाहरण बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से मांग की कि केवल बयानबाजी करने के बजाए गैस आपूर्ति को सुचारू बनाया जाए और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता और उद्योगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है।

देशभर में 40 करोड़ की साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़, 10 आरोपी काबू

गुरुग्राम (हिंस)। देशभर से 40 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस की टीमों ने भंडाफोड़ किया है। आरोपी इंवेस्टमेंट, लोन, डिजिटल अरेस्ट, साइबर स्लेवरी व क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों से चार लाख रुपए, 11 मोबाइल फोन व दो सिम कार्ड बरामद किए हैं। एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान की अगुवाई में साइबर क्राइम वेस्ट व साउथ थाना पुलिस की टीमों ने साइबर ठगी करने वालों पर शिकंजा कसा। उनके नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए दस आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चार लाख रुपए, 11 मोबाइल फोन व दो सिम कार्ड बरामद किए हैं।

कैथल : जिले की 40 हजार से अधिक पात्र महिलाओं ने उठाया लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, खातों में पहुंची सहायता राशि

कैथल (हिंस)। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना जिले में प्रभावी रूप से लागू हो रही है। जिले में अब तक 40 हजार 160 पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिनके खातों में प्रतिमाह सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जा रही है। उपायुक्त अपराजिता ने बुधवार को बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में शुरू की गई महिला कल्याण के उद्देश्य से वह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाना है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस राशि में से 1100 रुपए लाभार्थी के बैंक खाते में तथा शेष 1000 रुपए आरडी/एफडी के खाते में डाल जाते हैं। इससे महिलाओं को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। डीसी अपराजिता ने जिले की सभी पात्र महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि पात्र महिलाएं योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाएं। योजना महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमितेंद्र श्योकंद ने बताया कि सरकार द्वारा योजना का विस्तार करते हुए पूर्व निर्धारित नियमों के अलावा उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिनकी पीपीपी के अनुसार पारिवारिक की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार है या जो महिलाएं सफलतापूर्वक अपने बच्चों को कुपोषण से बाहर लेकर आई हैं। जिसकी पुष्टि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की माताएं तथा निपुण मिशन के अंतर्गत कक्षा एक से चार तक दक्षता हासिल करने वाले बच्चों की माताओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना की कहानी, लाभार्थियों की जुबानी योजना से लाभान्वित महिलाएं स्वयं अपने खर्चों का प्रबंधन करने में सक्षम हो गई हैं। लाभार्थी तनु का कहना है कि आर्थिक सहायता मिलने से वे अब अपने बच्चों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रही हैं। इससे परिवार के आवश्यक खर्चों को संभालना आसान हुआ है और जीवन स्तर में सुधार आया है। लाभार्थी शांति के अनुसार, इस पहल से उन्हें छोटे स्तर पर अपना काम शुरू करने का हौसला मिला है। उनका मानना है कि यह योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है।

पंजाब में आतंकी हमला टला, दो ग्रेनेड सहित दो व्यक्ति गिरफ्तार

चंडीगढ़ (हिंस)। काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) बठिंडा ने दो हैंड ग्रेनेडों सहित दो गुर्गों को गिरफ्तार करके संभावित आतंकी हमले को टालने का दावा किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बुधवार को चंडीगढ़ में बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बूटा सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपू निवासी गिल्लवाली (फिरोजपुर) और हरमंदर सिंह उर्फ निक्का निवासी मोठांवाली (मोगा) के रूप में हुई है। डीजीपी यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बरामद किए गए ग्रेनेड सीमा पार की अवैध सप्लाई-चेन का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती प्रदेश में शांति और सुरक्षा भंग करना था। डीजीपी ने कहा कि इस मॉड्यूल में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है। सहायक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ

पुलिस (एआईजी) सीआई बठिंडा अवनीत कौर सिद्धू ने कहा कि पुलिस टीमों को विश्वसनीय स्रोतों से पुख्ता सूचना मिली थी कि आतंकी मॉड्यूल से जुड़े दो कार्यकर्ताओं ने हैंड ग्रेनेड प्राप्त किए हैं। इस पुख्ता सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सीआई बठिंडा की पुलिस टीम ने मोगा-फिरोजपुर रोड से दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए। एआईजी ने कहा कि काउंटर इंटेलिजेंस टीमों की सतर्क एवं सक्रिय कार्रवाई के कारण एक अप्रिय घटना को नाकाम कर दिया गया है।

जैसलमेर में पाकिस्तानी सीमा पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, आसमान में गरजे रॉकेट

जैसलमेर (हिंस)। जैसलमेर में भारतीय सेना ने बैटलफील्ड थंडर अभ्यास के जरिए अपनी रॉकेट आर्टिलरी की ताकत का प्रदर्शन किया। पिनाका और बीएम-21 ग्रेड जैसे आधुनिक मल्टी-बैरल रॉकेट लांचरों ने सटीक और तेज हमलों से अपनी मारक क्षमता दिखाई। इस अभ्यास ने संदेश दिया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना की कोणार्क कोर ने ब्लैजिंग स्टील, डिसाइसिव इंपैक्ट थीम के तहत यह अभ्यास किया। इसमें रॉकेट आर्टिलरी यूनिट्स ने अपनी ऑपरेशनल तैयारी और समन्वय का प्रदर्शन किया। थार के आसमान में एक साथ कई रॉकेट दागे गए, जिससे पूरे क्षेत्र में सेना की ताकत का अहसास हुआ। जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में हुए इस अभ्यास के दौरान सैनिकों ने भीषण गर्मी और उड़ती धूल के बीच लगातार प्रशिक्षण लिया। मुख्य आकर्षण लंबी दूरी के लक्ष्यों को पूरी सटीकता से ध्वस्त करना रहा। यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि विभिन्न युद्ध प्रणालियों के बेहतर तालमेल की जांच भी थी। अभ्यास के दौरान ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम के साथ रॉकेट लांचरों के तालमेल को भी परखा गया। एक साथ दागे गए रॉकेटों की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी, जिसने सेना की तैयारियों का स्पष्ट संकेत दिया। इस अभ्यास ने दिखा दिया कि रेगिस्तानी इलाकों में भी भारतीय सेना की रॉकेट आर्टिलरी पूरी तरह सक्षम है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे इलाकों में सैचुरेशन फायर (पूरे क्षेत्र में एक साथ हमला) सबसे प्रभावी होता है, और भारतीय सेना इस क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है।

योगी सरकार के *नव निर्माण के नौ वर्ष* पूरे जनप्रतिनिधियों ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, गिनाईं उपलब्धियां

लखीमपुर खीरी (हिंस)। उप्र सरकार के *नव निर्माण के नौ वर्ष* पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन के तत्वावधान में 09 दिवसीय मेले और विकास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जहां एक ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोहा, वहीं सरकारी योजनाओं के संगम ने लाभार्थियों को कई सौगातें दी। विधायक योगेश वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार संग फीता काटकर व दीप जलाकर कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सरकार के *नव निर्माण के नौ वर्ष* पूर्ण होने पर केंद्रित लघु फिल्म देखी और सुनी गई। इससे पहले राजधानी लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखी और सुनी गई। कार्यक्रम का सफल संयोजन सीडीओ अभिषेक कुमार और उनकी टीम ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सदर योगेश वर्मा ने अपार समर्थन देने के लिए आमजनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 09 वर्षों में किसान के उत्थान के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देना, परंपरागत उद्यमिता को आगे बढ़ाया गया। मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए जो कार्य किए गए। आज प्रदेश विकास की उदाहरण बनकर उभरा है। भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने 09 वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेशवासियों की कल्याण और प्रदेश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए काम हुआ है। प्रदेश में आज कानून का राज है, जहां जनमानस सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज उप्र की कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे भारत में दी जाती है। कार्यक्रम में विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रेखांकित करते हुए कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम आदमी की जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है। सरकार ने अंत्योदय के मंत्र को धरातल पर उतारते हुए योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इस दौरान सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अफसरो के साथ सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए कि मेले में आने वाले व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का न केवल जानकारी दे बल्कि उन्हें योजना से जोड़कर उनके जीवन सुगम बनाया जाए। कलेक्ट्रेट में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा लगाई गई 09 दिवसीय विकास प्रदर्शनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, विधायक योगेश वर्मा व विनोद शंकर अवस्थी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल व सीडीओ अभिषेक कुमार मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदर्शनी में पीएम नरेन्द्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। इससे आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि प्रदर्शनी में किसानों, महिलाओं, युवाओं व वंचित वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और नवाचारों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। जनप्रतिनिधियों ने अफसरों संग लाभार्थियों को दी योजनाओं की सौगात, चेहरे खिले कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, विधायक योगेश वर्मा, और विनोद शंकर अवस्थी ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल व सीडीओ अभिषेक कुमार के साथ जिले के 1140 स्वयं सहायता समूहों को 03 करोड़ 42 लाख रुपए का रिवाल्विंग फंड सौंपा। कार्यक्रम में पांच लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड, पांच को पीएम आवास योजना शहरी, पांच को सीएम आवास योजना ग्रामीण, छह को विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत टूल किट, पांच को पीएम मातृत्व वंदना योजना की धनराशि और 10 को कृषि व उद्यान किट प्रदान की गई। खादी ग्रामोद्योग विभाग ने भी फर्नीचर, दोना-पत्तल, शटरिंग ट्रेड के लाभार्थियों को हितलाभ का वितरण किया।

राज्यसभा चुनाव में अनुपस्थिति पर कांग्रेस के तीन विधायकों से जवाब-तलब

पटना (हिंस)। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के तीन विधायकों की अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए उन्होंने कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद एवं मनोज विश्वास से दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। कपिलदेव प्रसाद यादव ने कहा कि दिनांक 16 मार्च 2026 को संपन्न राज्यसभा चुनाव के दौरान संबंधित विधायक मतदान प्रक्रिया से अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण महागठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान संबंधित विधायकों से मोबाइल के माध्यम से लगातार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन न तो कॉल रिसीव किया गया और बाद में उनका फोन स्विच ऑफ पाया गया। अनुशासन समिति अध्यक्ष ने तीनों विधायकों से इस संबंध में दो दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।

सम्राट चौधरी का एलान, जमुई में 6 हजार करोड़ की लागत से बनेगा स्टील प्लांट

पटना (हिंस)। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जमुई जिले में 6 हजार करोड़ रुपए की लागत से स्टील प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही भीमबांध और कुंड घाट को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई और नवादा पहुंचे उपमुख्यमंत्री चौधरी ने जमुई के लछुआर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में बुनियादी सुविधाओं का गंभीर अभाव था। उस समय सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं थीं। उन्होंने कहा कि तब राज्य में केवल 6 हजार किलोमीटर सड़कें थीं, जो अब बढ़कर 1 लाख 40 हजार किलोमीटर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट पहले लगभग 23 हजार करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। बिजली के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता

थे, अब यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हो गई है। राज्य में 22 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे लगभग 88 प्रतिशत परिवारों का बिजली बिल पिछले सात महीने से शून्य आ रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपए देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। आज जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं राज्य की अर्थव्यवस्था में 1 लाख 26 हजार करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें और पलायन पूरी तरह समाप्त हो सके। सम्राट चौधरी ने कहा कि जमुई की पहचान पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में होती थी, लेकिन एनडीए सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त कर यहां विकास का माहौल बनाया है। अब जमुई पर्यटन के क्षेत्र में भी उभर रहा है। कुंड घाट जलाशय का उद्घाटन किया गया है और बरनार जलाशय को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टील प्लांट और इथेनॉल प्लांट स्थापित होने के बाद लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं नवादा के आईटीआई मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नवादा की पहचान भी कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में थी, लेकिन अब यहां शांति और विकास का माहौल है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है और आज बिहार की सड़कों की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने बताया कि नवादा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और पानी की समस्या को दूर करने के लिए गंगा से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है।

नव वर्ष स्वागत को तैयार जयपुर 55 स्थानों पर होगी भव्य महाआरती

जयपुर (हिंस)। जयपुर में हिंदू नव वर्ष (चैत्र प्रतिपदा) को इस बार व्यापक स्तर पर उत्साह और आस्था के साथ मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के तत्वावधान में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। संस्थान के प्रदेश सचिव सोमकांत शर्मा ने बताया कि इस वर्ष विशेष अभियान के तहत 11 हजार *धर्म योद्धा* तैयार किए गए हैं। ये धर्म योद्धा शहर की कॉलोनियों, नगरों और बस्तियों में जाकर लोगों को हिंदू नव वर्ष मनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों के अंतर्गत चार स्थानों पर गज वंदन, सात स्थानों पर सामूहिक सूर्य वंदन तथा 50 से अधिक स्थानों पर सामूहिक महाआरती आयोजित की जाएगी। धर्म योद्धाओं की 1100 टोलियां बनाकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है। ये टीमें घर-घर जाकर नव संवत्सर के स्टीकर, पत्रक एवं ?

अंकित पताकाएं वितरित कर रही हैं। अब तक करीब 26 हजार मकानों पर पताकाएं लगाई जा चुकी हैं। गुरुवार को शहर के 11 जोनों के 55 से अधिक मंदिरों में सामूहिक महाआरती का आयोजन होगा। प्रमुख स्थानों में हीरापुरा का रजनी विहार मंदिर, मालवीय नगर केलिगिरी रोड स्थित शिव मंदिर, गोपालपुरा का शांति विहार शिव मंदिर, गोविंद नगर शिव मंदिर तथा भांकरोटा का शिव मंदिर शामिल हैं। हर मंदिर में 1100 दीपकों से आरती की जाएगी। इस प्रकार कुल मिलाकर 55 हजार से अधिक दीपकों से भव्य महाआरती का दृश्य सजेगा। हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं। गुरुवार को हीरापुरा स्थित रजनी विहार में विशेष प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।

सोना हुआ महंगा, चांदी की भी बढ़ी चमक

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान मजबूती का रुख नजर आ रहा है। बुधवार को कारोबार की शुरुआत में ही हाजिर सोने के भाव में 620 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 680 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी दर्ज की गई। इसी तरह चांदी भी 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगा हो गया। कीमत में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,58,090 रुपये से लेकर 1,58,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,44,910 रुपये से लेकर 1,45,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी उछाल आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,75,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,58,240 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,060 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,58,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,44,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,58,140 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,960 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,58,090 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,44,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,58,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,44,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,44,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,58,240 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,45,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,44,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,58,240 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,45,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,58,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,44,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

न्यूज़ ब्रीफ

वैश्विक तेल बाजार में उबाल, 100 डालर के पार पहुंचा कच्चा तेल, भारत में अभी भी राहत

नई दिल्ली। ईरान और इजरायल के बीच छिड़े भीषण युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में कोहराम मचा दिया है। मिडिल-ईस्ट से उठ रही युद्ध की लपटों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। 23 फरवरी 2026 तक जो कीमतें वैश्विक स्तर पर सामान्य थीं, उनमें अब भारी उछाल आ चुका है। ब्रेंट क्रूड ने 71 डालर प्रति बैरल के स्तर से सीधी छलांग लगाते हुए 100 डालर प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर लिया है। यह लगभग 45 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में युद्ध की गंभीर आशंकाओं को साफ दर्शाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की इस आग ने आम आदमी की जेब जलानी शुरू कर दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर पेट्रोल की औसत कीमतें 1.20 डालर प्रति लीटर से बढ़कर 1.27 डालर पर पहुंच गई हैं। वहीं, डीजल ने और भी तेज रफ्तार दिखाई है, जिसकी औसत कीमत 1.20 डालर से उछलकर 1.33 डालर प्रति लीटर पर जा पहुंची है। ये आंकड़े बताते हैं कि डीजल पर युद्ध की मार पेट्रोल के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी पड़ी है। हैरानी की बात यह है कि भारत, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों में अभी तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

गैलेक्सी ए 37 और गैलेक्सी ए57 के लांच की तैयारी

नई दिल्ली। सैमसंग कंपनी अपने दो नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी ए 37 और सैमसंग गैलेक्सी ए57 जल्द लान्च हो सकते है। इनके हैंड्स-आन वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गए हैं। इन वीडियो को एक्स पर एक यूज ने शेयर किया है, जिससे फोन्स के डिजाइन और कुछ फीचर्स के बारे में अहम जानकारी मिली है। वीडियो के अनुसार दोनों स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएंगे, जिसमें कैमरे वर्टिकल लाइन में लगाए गए हैं। फोन के राइट साइड में पावर और वाल्यूम बटन के साथ कंपनी का खास की इस्लेंड डिजाइन भी देखने को मिलता है। दोनों डिवाइस फुल एचडी प्लस अमोलेड डिस्प्ले और 120 एचझेड रिफ्रेश रेट के साथ पेश किए जा सकते हैं। लीक वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी ए 37 का ग्रीन कलर वेरिएंट दिखाई दिया है। यह फोन फ्लैट डिस्प्ले और अपेक्षाकृत मोटे बेजल्स के साथ आ सकता है। डिस्प्ले में सेल्फी कैमरे के लिए पंच-होल कटआउट दिया गया है। इसके पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा यूनिट और एलईडी फ्लैश मौजूद है। वहीं फोन के निचले हिस्से में सैमसंग का लोगो भी दिखाई देता है। दूसरी ओर सैमसंग गैलेक्सी ए 57 का पर्पल कलर वेरिएंट वीडियो में नजर आया है।

नाटो से मदद न मिलने पर भड़के ट्रंप बोले- अकेले लड़ेंगे, चीन का दौरा भी टाल दिया

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने के अंत में होने वाला अपना प्रस्तावित चीन दौरा

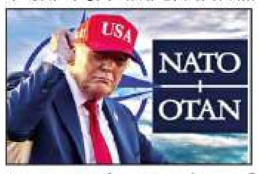

आधिकारिक रूप से टाल दिया है। ईरान के साथ जारी युद्ध और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में आए गतिरोध के बीच व्हाइट हाउस ने यह बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि अब वह अगले पांच या छह हफ्तों में चीन की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस देरी के महत्व को कम बताते हुए कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनके कामकाजी और व्यक्तिगत रिश्ते बहुत मजबूत हैं और शी जिनपिंग भी उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरे के टलने के पीछे की असली वजह होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उपजा विवाद माना जा रहा है। ट्रंप ने पहले संकेत दिया था कि उनकी चीन यात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि बीजिंग होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खुलवाने में वाशिंगटन की मदद करता है या नहीं। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के जवाब में ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस समुद्री मार्ग को बाधित कर दिया है। हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप के दौरे का इस समुद्री मार्ग के विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर अपनी भड़ास निकालते हुए नाटो और अपने अन्य प्रमुख सहयोगियों पर भी निशाना साधा है।

पावरिका लिमिटेड का आईपीओ 24 मार्च को खुलेगा, दो अप्रैल को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

डीजल जेन सेट का उत्पादन करने के साथ ही विंड पावर बिजनेस में भी काम शुरू करने वाली कंपनी पावरिका लिमिटेड ने अपने आईपीओ की लान्चिंग का ऐलान कर दिया है। कंपनी का 1,100 करोड़ रुपये का आईपीओ 24 मार्च को खुलेगा। इस आईपीओ में निवेशक 27 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 30 मार्च को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि एक अप्रैल को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर दो अप्रैल को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 375 रुपये से लेकर 395 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 37 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लाट यानी 37 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,615 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,89,995 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लाट में 481 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत 5 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 2,78,48,100 शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें 700 करोड़ रुपये के 1,77,21,518 नए शेयर और 400 करोड़ रुपये के 1,01,26,582 शेयर आफर फार सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि एमयूजीएफ इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत में मामूली उतार चढ़ाव होता रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 106.45 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 226.11 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में घट कर 175.83 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक कंपनी को 134.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका है। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी मामूली उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में इसे 2,422.42 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घट कर 2,356.77 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 2,710.93 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक कंपनी को 1,474.87 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज के बोझ में भी उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी पर 278.88 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में कम होकर 177.52 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 300.80 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ 571.95 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इस अवधि में कंपनी के रिजर्व और सरप्लस में लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में ये 777.88 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2023-24 में बढ़ कर 898.67 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 1,070.95 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक ये 1,158.99 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा हुआ है। कंपनी के ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमार्टाइजेशन) की बात करें तो 2022-23 में ये 333.21 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2023-24 में बढ़ कर 362.45 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का ईबीआईटीडीए घट कर 345.66 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में 30 सितंबर 2025 तक ये 220.42 करोड़ रुपये के स्तर पर था।

इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए मंत्रालय 23 मार्च को करेगा खुली बैठक

नई दिल्ली

इस्पात मंत्रालय 23 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के नेताजी नगर स्थित जीपीओए-3 की तीसरी मंजिल पर स्थित इस्पात कक्ष में एक खुली बैठक का आयोजन करेगा। इस बैठक में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस्पात मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि कंपनियां और संगठन संबंधित अपने मुद्दों को इस बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस बैठक में भाग लेने के लिए पर ईमेल भेजकर उपरोक्त तिथि के लिए निश्चित समय स्लाट प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रायल के मुताबिक ई-मेल भेजते समय निम्नलिखित जानकारी शामिल की जा सकती है:- कंपनी/एसोसिएशन का नाम, उद्योग और उत्पाद का प्रकार, जैसे आटोमोबाइल , यरोस्पेस, दूरसंचार, रक्षा, आदि। यह समस्या एसआईएमएस/एसएआरएएल एसआईएमएस और क्यूसीओ छूट से संबंधित है। यदि कोई हो तो एसआईएमएस/एसएआरएएल एसआईएमएस/क्यूसीओ छूट आवेदन का संदर्भ दें। समस्या का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 50 शब्द), प्रतिभागी का नाम और पदनाम (किसी तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व स्वीकार्य नहीं है) और प्रतिभागी की संपर्क जानकारी (मोबाइल नंबर और ईमेल) शामिल है। मंत्रालय के मुताबिक इस खुली बैठक का आयोजन सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा और समय-सीमा की जानकारी ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। व्यवस्था संबंधी परेशानियों के कारण बिना पूर्व बुकिंग के प्रवेश संभव नहीं होगा और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संगठन से केवल एक प्रतिनिधि को ही अनुमति दी जाएगी। इस्पात मंत्रालय के मुताबिक संबंधित पक्ष को यह सलाह दी जाती है कि इस्पात के आयात के लिए एसआईएमएस/एसएआरएएल एसआईएमएस/क्यूसीओ छूट से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही कोई भी कंपनी या संस्था 20 मार्च को दोपहर तीन बजे तक उपरोक्त ईमेल पते पर अपना अनुरोध भेजकर समय-सीमा की पुष्टि करवा सकती है।

वनप्लस नोर्ड 6 और वनप्लस नोर्ड सीई 6 जल्द होगा लांच

नई दिल्ली । वनप्लस अपने नए स्मार्टफोन वनप्लस नोर्ड 6 और वनप्लस नोर्ड सीई 6 को लान्च करने की तैयारी में है। नोर्ड सीई 6 को भारत के बीआईएस प्लेटफार्म पर देखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि यह फोन जल्द भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। वहीं नोर्ड 6 को कई अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर स्पाट किया गया है, जिससे इसके भी जल्द लान्च होने की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नोर्ड 6 को 2026 की पहली तिमाही के आसपास पेश किया जा सकता है। कंपनी आमतौर पर अपनी नोर्ड सीरीज के नए माडल समर इवेंट के दौरान लान्च करती है, इसलिए संभावना है कि यह स्मार्टफोन भी इसी समय बाजार में आए। लीक्स के मुताबिक वनप्लस नोर्ड 6 में 6.78 इंच की अमोलेड डिस्प्ले दी जा सकती है, जो 1.5के रेजोल्यूशन और 165 एचझेड तक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकती है। इसमें पावरफुल स्नैपड्रेगन 8एस जेन 4 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जो बेहतर परफार्मेंस देने में सक्षम होगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा और लगभग 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा फोन में 9000 एमएएच तक की बड़ी बैटरी दिए जाने की भी चर्चा है। दूसरी ओर वनप्लसनोर्ड सीई 6 6 में करीब 6.78 इंच की फुल एचडी+ ओलेड डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जो 144एचझेड रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकती है। इसमें स्नैपड्रेगन 8एस जेन 4 या स्नैपड्रेगन 7 सीरीज का नया चिपसेट दिया जा सकता है।

सरकार ने हवाई यात्रा को और आसान बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

अब 60 फीसदी मनपंसद सीटें चुन सकेंगे यात्री, अतिरिक्त शुल्क वसूली पर भी लगाम

नई दिल्ली

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को हवाई यात्रा को और आसान बनाने के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार विमानन कंपनियों से कहा कि किसी भी फ्लाइट में कम से कम 60 फीसदी सीटें अतिरिक्त शुल्क के बगैर उपलब्ध करानी होंगी, ताकि सभी यात्रियों को बराबरी का मौका मिले। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एयरलाइन यात्रियों के लिए पारदर्शी और सुविधाजनक हो। नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि एक ही पीएनआर (पैसेंजर नेम रिकार्ड) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ में बैठाया जाए। इसके तहत यह कोशिश की जाए कि वे पास-पास की सीटों पर बैठ सकें। इससे परिवार या समूह में सफर करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। ये निर्देश घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं, जब सीट चयन सहित विभिन्न सेवाओं के लिए विमानन कंपनियां अधिक शुल्क वसूल रही हैं। डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि हर उड़ान में कम से कम 60 फीसदी सीट बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं, ताकि निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित हो सके। नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए निर्देशों में 60 फीसदी सीट बिना अतिरिक्त शुल्क, परिवारों के लिए साथ बैठने की व्यवस्था और खेल उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र एवं पालतू जानवरों के परिवहन के लिए स्पष्ट तथा पारदर्शी नियम शामिल है। मंत्री ने बताया कि देरी और टिकट रद्द कराने की स्थिति में भी यात्री अधिकारों के प्रवर्तन को मजबूत किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि एयरलाइन वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशनों, बुकिंग प्लेटफार्मों और हवाई अड्डे के काउंटरों पर यात्रियों के अधिकारों का प्रमुखता से प्रदर्शन के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों के अधिकारों की स्पष्ट जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाने को कहा गया है, ताकि व्यापक पहुंच।

ग्लोबल मार्केट से पाजिटिव संकेत, एशिया में भी तेजी का रुख

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से पाजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान खरीदारी होती रही। एशियाई बाजार में भी आमतौर पर खरीदारी का रुख बना हुआ है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीतिगत ऐलान करने वाला है। इस ऐलान के पहले अमेरिकी बाजार में निवेशक सतर्क मुद्रा में कारोबार करते रहे। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 6,716.09 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 105.35 अंक यानी 0.47 प्रतिशत उछल कर 22,479.53 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 233.69 अंक यानी 0.50 प्रतिशत की छलांग लगा कर 47,226.95

अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान सकारात्मक माहौल बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.83 प्रतिशत की तेजी के साथ 10,403.60 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.48 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,974.49 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 166.91 अंक यानी 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,730.92 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशिया में भी आमतौर पर खरीदारी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। एशिया के नौ बाजार में से सात के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि दो सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.40 प्रतिशत टूट कर 4,033.62 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 0.18 प्रतिशत फिसल कर 25,823 अंक के स्तर पर आ गया है। दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 150.50 अंक यानी 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,732.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.04 प्रतिशत की मजबूती के साथ 4,987.07 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। कोस्पी इंडेक्स ने जोरदार छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 224.13 अंक यानी 3.97 प्रतिशत उछल कर 5,864.61 अंक के स्तर पर आ गया है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स 1,329.61 अंक यानी 2.48 प्रतिशत की बढ़त के साथ 55,030 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ताइवान वेटेड इंडेक्स 479.54 अंक यानी 1.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 34,316.11 अंक के स्तर पर, जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 84.55 अंक यानी 1.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,106.84 अंक के स्तर पर और सेट कंपोजिट इंडेक्स 1.18 प्रतिशत की छलांग लगा कर 1,450.74 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

बल्लेबाज पोप को भरोसा–एशेज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी दिखाएंगे अपना सर्वश्रेष्ठ

नई दिल्ली

आस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप का मानना है कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी आना बाकी है। इस सीरीज में इंग्लैंड को 4–1 से हार मिली थी और खराब फार्म के चलते पोप को टीम से बाहर भी होना पड़ा था। 28 वर्षीय बल्लेबाज ने आस्ट्रेलिया में खेले शुरुआती तीन टेस्ट मैचों में कुल 125 रन बनाए, जो उनके स्तर के हिसाब से काफी निराशाजनक रहा।

दौरे के बाद जब इंग्लैंड टीम की प्रतिबद्धता पर सवाल उठे तब पोप ने इसे आत्ममंथन और नए सिरे से तैयारी का मौका माना। अब उनका पूरा ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर है, ताकि आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम में वापसी कर सकें।

एशेज के दौरान छह पारियों में से एक में भी पोप पचास रन नहीं बना पाए और चौथे व पांचवें टेस्ट में उन्हें बेंच पर बैठा दिया गया था। उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में जैकब बेथेल को शामिल किया गया था। आईसीसी के अनुसार सरे के प्री–सीजन मीडिया डे पर पोप ने कहा कि मुझे अपनी स्थिति का पता था। टीम से बाहर होना मुश्किल था, लेकिन उस समय यह सही फैसला था।

उन्होंने आगे कहा कि बातचीत का मकसद बस यही था कि वापस जाकर खूब रन बनाऊं और अगर इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में जगह न मिले तो यह सुनिश्चित करूं कि मैं देश का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित होऊं। अगर कुछ होता है तो यह सुनिश्चित करना है कि मेरी जगह लेने के लिए मैं ही सही खिलाड़ी हूं। मैंने बहुत टेस्ट क्रिकेट खेला है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मेरे बल्लेबाजी के सर्वश्रेष्ठ दिन अभी आने बाकी हैं।

पोप ने इंग्लैंड एशेज जीतने को लेकर गंभीर नहीं था आरोपों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक लोकप्रिय टीम बनना चाहते हैं और दुर्भाग्य से आस्ट्रेलिया में हमारे प्रदर्शन ने ऐसा होने नहीं दिया। मैं समझ सकता हूं कि लोगों को ऐसा क्यों लगा। यह धारणा कि हम बेफिक्र थे, शायद सबसे मुश्किल बात थी। हर खिलाड़ी एशेज सीरीज के दबाव को संभालने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था।

उन्होंने कहा कि हर कोई सिर्फ जीतना चाहता था। मुझे लगता है कि शायद कभी–कभी हमारे मन में यही बात थी कि हम टेस्ट मैच के दबाव को कम करने के लिए, जैसा कि हमने पिछले दौरों में किया था, इसे एक सामान्य सीरीज की तरह लें ताकि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हो पाया।

न्यूज ब्रीफ

ब्रैड हैडिन को न्यू साउथ वेल्स पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया

नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैड हैडिन को न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) की

पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वे ग्रेग शिप्पर्ड की जगह लेंगे और जून से अपना कार्यभार संभालेंगे। ग्रेग का कार्यकाल उनके अनुबंध में एक साल शेष रहते हुए ही समाप्त कर दिया गया था। 48 वर्षीय हैडिन नवंबर 2014 में क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स के लिए अपना आखिरी मैच खेलने के बाद पहली बार वापसी कर रहे हैं। हैडिन अपने साथ कोचिंग का व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। हैडिन ने इससे पहले डैरेन लेहमैन और जस्टिन लैंगर के मार्गदर्शन में आस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के सहायक और फील्डिंग कोच के रूप में काम किया है। वह वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग में रिकी पोंटिंग की कोचिंग वाली पंजाब किंग्स के सहायक कोच हैं और इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के भी सहायक कोच रह चुके हैं। हैडिन ने एक बयान में कहा, एनएसडब्ल्यू क्रिकेट मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है और मुख्य कोच के रूप में इस टीम में फिर से शामिल होना मेरे और मेरे परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा, मैं हमारे मौजूदा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं ताकि एनएसडब्ल्यू क्रिकेट में एक नई जान फूंकी जा सके और एक ऐसी टीम बनाई जा सके जिसकी खेल शैली दमदार और विशिष्ट हो, जिस पर हम सभी गर्व कर सकें। क्रिकेट एनएसडब्ल्यू के मुख्य कार्यकारी ली जर्मन ने कहा कि ब्रैड एक बेहद सम्मानित कोच हैं, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी स्तर पर अनुभव है। साथ ही उन्हें एनएसडब्ल्यू की खेल शैली की गहरी समझ भी है। हमें गर्व है कि ब्रैड हमारी ब्लूज टीम का मार्गदर्शन करेंगे और हम जून से उनके साथ काम करने
के लिए उत्सुक हैं।

विराट आईपीएल के लिए बेंगलुरु पहुंचकर अपनी टीम आरसीबी से जुड़े

बेंगलुरु। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल के 19 सत्र में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचकर

अपनी टीम टीम रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से जुड़ गये हैं। विराट के यहां पहुंचने के साथ ही आरसीबी के खेमे में उत्साह की लहर फैल गयी। विराट का प्रशंसकों के साथ ही टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों को भी इंतजार था।, बेंगलुरु पहुंचने से पहले कोहली इंग्लैंड में थे पर वहां भी वह तैयारी जारी रखे थे। उन्होंने अपने अभ्यास की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी की थी जिसे आरसीबी ने भी साझा किया है। कोहली के टीम से जुड़ने के बाद अभ्यास सत्र में तेजी आने की उम्मीद है। आरसीबी को इस सत्र में अपना पहला मैच 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से खेलना है। इससे वह खिताब बराकरार रखने के इरादे से उतरेगी। पिछले सत्र में उसने रजत पाटीदार की कप्तानी में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार खिताब जीता था। आरसीबी को चैंपियन बनाने में विराट की अहम भूमिका रही है। विराट ने पिछले सत्र में 15 मैचों में 54.75 की औसत और 144.71 की स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक लगाये थे। ऐसे में टीम प्रबंधन चाहेगा कि वह इस बार भी अधिक से अधिक रन बनाकर टीम को जीत दिलायें। विराट शुरुआती सत्र से ही आरसीबी से जुड़े हैं। उनके प्रदर्शन में निरंतरता रहती है। लगभग हर साल वह टीम की ओर से सबसे अधिक रन बनाते आये हैं। कोहली आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज हैं।

आरसीबी बन सकती है सबसे महंगी आईपीएल टीम

मुम्बई। आईपीएल टीम रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की बिक्री प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गयी

है। अगर ये सौदा हुआ तो आरसीबी सबसे महंगी टीमों में शामिल हो जाएगी। टीम की बिक्री प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है क्योंकि इसकी कीमत 2 अरब डालर करीब 18488 करोड़ रुपया तक पहुंच गयी है। अगर ये सौदा होता है, तो आरसीबी सबसे महंगी आईपीएल टीम होने के साथ ही दुनिया की सबसे कीमतों टीमों मे शामिल हो जाएगी। अभी इसका मालिकाना अधिकार डियाजियो की यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास है। वहीं इसे खरीदने के लिए दो बड़े निवेशकों के बीच मुकाबला है। शुरुआत में पांच निवेशक थे पर अब दो ही रह गये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीडन की ईक्यूटी कंपनी और मणिपाल ग्रुप मिलकर इसके लिए बोली लगा रहा है। वहीं इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के सह–मालिक ग्लेजर्स ने करीब 1.8 अरब डालर की शुरुआती (नान–बाइंडिंग) बोली लगाई थी पर बाद में वह पीछे हट गये। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने भी शुरुआत में इसे खरीदने बोली लगायी थी पर बाद में वह पीछे हट गये।

हाकी विश्व कप : चुनौतीपूर्ण पूल डी में भारत कोच मारिजने बोले– प्रदर्शन पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली

एफआईएच महिला हाकी विश्व कप 2026 के लिए अपनी क्वालिफिकेशन पक्की करने के बाद भारतीय महिला हाकी टीम मंगलवार शाम को टूर्नामेंट के ड्रा की घोषणा के बाद इस बड़े इवेंट की तैयारी कर रही है। आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को पूल डी में इंग्लैंड, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। यह टूर्नामेंट इस साल अगस्त में होने वाला है।

इस ग्रुप में चीन सबसे ऊंची रैंक वाली टीम है, जो अभी दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत की हाल की प्रतिद्वंद्वी और एफआईएच हाकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर्स (हैदराबाद, तेलंगाना) की विजेता टीम इंग्लैंड छठे स्थान पर है, जबकि भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः नौवें और उन्नीसवें स्थान पर हैं। खेलने की बिल्कुल अलग–अलग शैलियों के साथ यह ग्रुप भारतीय टीम के लिए एक रोमांचक चुनौती पेश करेगा। आगे आने वाली कड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए टीम के मुख्य कोच सजोर्ड मारिजने को पूरा भरोसा है कि उनकी टीम लगातार अपनी हाकी शैली का प्रदर्शन कर सकती है।

हाकी इंडिया की ओर से जारी बयान में मारिजने ने कहा कि यह एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी और संतुलित पूल है। इसमें इंग्लैंड और चीन जैसी टीमें हैं जो अलग–अलग शैलियां और ढेर सारा अनुभव लेकर आती हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की महिला राष्ट्रीय हाकी टीम हमेशा अप्रत्याशित होती है और अपने दिन पर बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह ड्रा की बात नहीं है, यह इस बात की बात है कि हम मैदान पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। विश्व कप में, हर मैच में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। हम सभी विरोधी टीमों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अपनी शैली की हाकी को निरंतरता और साहस के साथ खेलने पर है। हाल ही में हैदराबाद (तेलंगाना) में संपन्न हुए एफआईएच हाकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर्स में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि फाइनल में उसे इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में मिली इस हार के बावजूद टीम के लिए कई सकारात्मक पहलू रहे। टीम ने इस टूर्नामेंट का समापन दूसरे सबसे ज्यादा गोल (11 गोल) करने वाली टीम के तौर पर किया, जिनमें से छह गोल पेनल्टी कार्नर से आए थे।

टूर्नामेंट पर विचार करते हुए कोच ने टीम को लगातार सुधार करने और निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया और इस बात पर जोर दिया कि वे मैदान के दोनों छोरों पर ज्यादा सटीक खेलें। उन्होंने कहा कि हमने आगे बढ़कर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने मौकों को गोल में बदलने पर ध्यान दें, चाहे वे फील्ड गोल हों या पेनल्टी कार्नर। इसके अलावा, हमें रक्षात्मक रूप से भी अपनी रणनीतियों पर काम करते रहना होगा।

टूर्नामेंट का इंतजार करते हुए और तैयारियों पर रोशनी डालते हुए सजोर्ड मारिजने ने कहा कि हमारा यूएसए और अर्जेंटीना का दौरा है, न्यूजीलैंड में नेशंस कप है और जर्मनी में प्रैक्टिस मैच हैं। हम नीदरलैंड्स में भी कुछ मैच खेलेंगे। ये तय मैच और हमारे कैंप मिलकर हमें विश्व कप और एशियन गेम्स के लिए तैयार होने के लिए मैचों और प्रशिक्षण का एक बहुत अच्छा मेल देते हैं।

कान्वे, सीयर्स और फर्ग्यूसन के शानदार प्रदर्शन से दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड जीती

आकलैंड

डेवोन कान्वे की आक्रामक अर्धशतकीय पारी के बाद बेन सीयर्स और लाकी फर्ग्यूसन की अच्छी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मुकाबले में मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका को 68 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान कीवी टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाये थे।

जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम 15.3 ओवर में ही केवल 107 रन बनाकर आउट हो गयी। इस प्रकार कीवी टीम पांच मैचों की सीरीज में वापसी की है। अब सीरीज 1–1 से बराबरी पर आ गयी है। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम जीती थी।

दक्षिण अफ्रीका को 68 रनों से हराया

इस दूसरे मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पायी। बेन सीयर्स और लाकी फर्ग्यूसन ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तीन–तीन विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेला पाया। उसने अपने अंतिम छह विकेट केवल 40 रन पर ही खो दिये। केवल जार्ज लिंडे ही 33 रन बना पाये। वहीं हाल में विश्वकप में अंतिम ग्यारह में जगह पाने में असफल रहे कान्वे ने 49 गेंद में 5 चौके और 2 छक्के लगाकर 60 रन बनाए। उनके अलावा जोश क्लार्कसन ने भी 26 रन बनाये। निक केली ने 21 और कप्तान मिचेल सैंटनर ने 20 रनों का योगदान दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीकी कप्तान केशव महाराज ने हार के लिए खराब बल्लेबाजी को जिम्मेदार बताया है।

रियल मैड्रिड सहित तीन टीमें चैम्पयंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची

नई दिल्ली। विनीसियस जूनियर के शानदार प्रदर्शन से रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को 2–1 से हराकर यूईएफए चैम्पयंस लीग फुटबाल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। स्पेनिश क्लब मैड्रिड से मिली हार के साथ ही मैनचेस्टर सिटी मुकाबले से बाहर हो गयी। वहीं आर्सेनल और पेरिस सेंट–जर्मेन (पीएसजी) भी अपने–अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी हैं। रियल मैड्रिड की ओर से विनीसियस ने 2 गोल कर टीम को जीत दिलायी की। विनीसियस ने अपनी टीम की ओर से दोनो गोल दागे। वहीं मैनचेस्टर सिटी की तरफ से एकमात्र गोल एर्लिंग हालैंड ने किया। इस हार के साथ ही कोच पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर लगातार तीसरे सत्र में भी मैड्रिड के सामने टिक नहीं पायी। वहीं एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने बायर लेवरकुसेन को 2–0 से हराने के साथ ही कुल स्कोर 3–1 से जीत हासिल की। उसकी ओर से एबेरेची एजे ने शुरुआती गोलकर टीम को बढ़त दियायी जबकि डेक्लान राइस ने दूसरा गोल दागा। एक अन्य मुकाबले में पेरिस सेंट–जर्मेन ने चेल्सी को 3–0 से हराकर कुल स्कोर 8–2 से आसान जीत जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनायी। उसकी ओर से ब्रैडली बारकोला और सेनी मायुलु ने गोल दागे।

वेस्टइंडीज सीरीज से पहले सोफी मोलिनक्स अपनी हर भूमिका निभाने के लिए तैयार

नई दिल्ली

आस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी मोलिनक्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ व्हाइट–बाल सीरीज के लिए खुद को तैयार बताया है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

टी–20 सीरीज से दोनों टीमें आगामी आईसीसी महिला टी–20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी तैयारियों को और तेज करने का लक्ष्य रखेंगी। आस्ट्रेलिया को ग्रुप ए में भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स जैसी टीमों के साथ रखा गया है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्काटलैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ग्रुप बी का हिस्सा हैं।

मोलिनक्स पीठ की चोट के कारण घर पर भारत के खिलाफ खेले गए आखिरी वनडे मैचों में नहीं खेल पाईं थीं, लेकिन कैरेबियन चुनौती से पहले वह पूरी तरह से फिट होने के करीब हैं।

आईसीसी के अनुसार मोलिनक्स ने मंगलवार को सेंट विंसेंट में कहा कि यह निश्चित है, मैं अपनी भूमिका निभाने और मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हूं। मैं लड़कियों के साथ मैदान में वापस आने के लिए उत्सुक हूं। हालांकि मोलिनक्स ने यह

स्पष्ट नहीं किया कि उपलब्धता के अलावा वह क्या भूमिका निभाएंगी।

यह देखना बाकी है कि मोलिनक्स सभी छह व्हाइट–बाल मैचों में खेलेंगी या नहीं। क्योंकि, उन्होंने संकेत दिया है कि टी–20 मैचों के बाद खेले जाने वाले 50 ओवर के मुकाबलों से उन्हें आराम दिया जा सकता है ताकि जून में होने वाले टी–20 विश्व कप के लिए उनका शरीर तैयार हो सके।

मोलिनक्स ने आगे कहा कि यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है क्योंकि टी–20 विश्व कप से पहले हमारे पास ज्यादा मैच नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा कि हर मैच बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

वेस्टइंडीज इस सीरीज को टी–20 विश्व कप की तैयारी के तौर पर देखेगी और आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों के लिए पूरी ताकत के साथ उतरेगी।

टीम की कप्तान हेली मैथ्यूज ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और मुझे लगता है कि यह इस बात का अच्छा परीक्षण होगा कि हम एक टीम के रूप में इस समय कहां हैं। उम्मीद है कि हम कुछ अच्छे परिणाम देख पाएंगे और इस सीरीज से बहुत सारी सकारात्मक बातें सीख पाएंगे।

सीरीज कार्यक्रम

पहला टी–20 मैच : 19 मार्च, सेंट विंसेंट।

दूसरा टी–20 मैच : 21 मार्च, सेंट विंसेंट।

तीसरा टी–20 मैच : 23 मार्च, सेंट विंसेंट।

पहला वनडे : 27 मार्च, सेंट किट्स।
दूसरा वनडे : 29 मार्च, सेंट किट्स।
तीसरा वनडे : 2 अप्रैल, सेंट किट्स।

रायगढ़ स्टेडियम में 19 मार्च से शुरू होगा एमएसपी कार्डिनल कप सीजन 9

रायगढ़

छत्तीसगढ़ के टेनिस बाल क्रिकेट के प्रेमियों के लिए इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म होने वाली हैं। 19 मार्च से एमएसपी कार्डिनल कप सीजन 9 अपने पूरे वैभव और भव्यता के साथ लौटने के लिए तैयार है। यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि देश के कोने–कोने से आने वाले खिलाड़ियों के लिए अपनी किस्मत और हुनर को आजमाने का एक महामंच है।

कार्डिनल कप आयोजन समिति ने प्रेसवार्ता में टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से बताया। टूर्नामेंट नाक आउट सिस्टम से खेला जाएगा। जिसमें कुल 32 मैच होंगे। हर दिन चार मैच होंगे और हर मैच 8–8 ओवर का होगा। सेमीफाइनल और फाइनल मैच 12 ओवर का खेला जाएंगे। प्रशासन 11 और पत्रकार 11 के मैच से टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा।सीजन 9 की तैयारियों को लेकर आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि इस बार मैदान की सजावट, पिच की गुणवत्ता और प्रकाश व्यवस्था को पिछले सभी आठ सीजनों से बेहतर बनाया गया है।

टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें शिरकत कर रही हैं। इन टीमों का चयन काफी कड़े मापदंडों के आधार पर किया गया है। कार्डिनल कप की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें किसी एक क्षेत्र के नहीं, बल्कि भारत के कोने–कोने से खिलाड़ी आ रहे हैं। मुंबई के तेजतर्रार टेनिस क्रिकेट स्टार्स से लेकर उत्तर भारत के धाकड़ बल्लेबाजों और मध्य भारत के चतुर गेंदबाजों तक, यहाँ विविधता में एकता का नजारा दिखेगा।

एमएसपी कार्निडल कप की आयोजन समिति कार्डिनल रोटी बैंक ने

इस बार इनामी राशि में भारी बढ़ोतरी की है। प्रथम पुरस्कार अपने नाम करने वाली टीम को दो लाख रुपये की भारी–भरकम नकद राशि और एक भव्य ट्राफी प्रदान की जाएगी।फाइनल में कड़ी टक्कर देकर दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को एक लाख रुपये से सम्मानित किया जाएगा।

हर मैच में मैन आफ द मैच, सर्वश्रेष्ठ अनुशासित टीम, और टूर्नामेंट के अंत में मैन आफ द सीरीज के लिए विशेष उपहार और नकद पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। मैदान में मैच का आनंद लेने आए दर्शकों के लिए आयोजन समिति ने आकर्षक उपहार रखें हैं।

कार्डिनल रोटी बैंक के अध्यक्ष अरुण उपाध्याय कहते हैं कि खेल दर्शकों के बिना अधूरा है। इसलिए, मैदान में आने वाले दर्शकों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बाउंड्री लाइन के बाहर बैठने वाले दर्शकों के लिए कैच पकड़ो, इनाम जीतो जैसे कई छोटे कान्टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक मैच के दौरान और फाइनल के दिन मैदान में मौजूद भाग्यशाली दर्शकों को आकर्षक उपहार (गैजेट्स, खेल किट और अन्य सरप्राइज) दिए जाएंगे।

एमएसपी जो कि इस बार के कार्डिनल कप की टाइटल स्पान्सर है के चीफ आपरेटिंग आफिसर बीके सिंह ने बताया कि हम चाहते हैं कि टेनिस बाल क्रिकेट को भी वही सम्मान मिले जो लेदर बाल क्रिकेट को मिलता है।

आयोजन समिति के सदस्यों में अजय पटेल, प्रदीप प्रधान, विशाल चंद्रा,यश पटेल ,मयूर मोटवानी, प्रदीप बाखला, राजेन्द्र पटेल, किशन साहू,अमित दीक्षित, अभिलाष पंडा,संजू साव,महेश, दिनेश मालाकार, मनोज साहा,अमित जाना,आशीष डनसेना, एवं समिति के सदस्यों ने पूरे दो महीने तक इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मेहनत की है।

सिगरेट से हुक्का ज्यादा खतरनाक...

इन दिनों हर छोटे बड़े शहरों और मॉल्स में हुक्का बार या शीशा लाउंज पॉपुलर होते नजर आ रहे हैं। युवा हुक्के का एक कश नहीं बल्कि हजार कश लेते हुए दिखते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि हुक्का पीना सिगरेट पीने के मुकाबले बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता।

लेकिन हुक्के से खींचा गया तंबाकू का धुआं पानी से होता हुआ एक लंबे होज पाइप के जरिए फेफड़ों तक पहुंचता है। पानी के बरतन से होते हुए आने के कारण ही यह एक आम भ्रांति है कि हुक्के का धुआं हानिकारक नहीं होता। सच यह है कि हुक्के से निकलने वाला धुआं सिगरेट या बीड़ी के धुएं से अधिक घातक होता है। हुक्का पीना सिगरेट की ही तरह हानिकारक है क्योंकि दोनों उत्पाद के अंत में कार्सिनोजन लगा रहता है जो कि एक कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है।

हुक्के का स्वाद बदलने के लिए केवल उसमें फ्रूट सीरप मिलाया जाता है जिससे उसके फ्लेवर में बदलाव आ जाता है। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हुक्के में किसी भी प्रकार का फल मिलाया गया हो। इसलिए यह आशा न करें कि हुक्के को पी कर आपको विटामिन मिलेगा।

सीने में जलन को ऐसे दूर करता है बेकिंग सोडा

एसिडिटी होने पर कई बार आपको भोजन नली या सीने में जलन की महसूस होती है। कभी-कभार ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप लगातार इस तरह की जलन महसूस करते हैं तो यह एक गंभीर समस्या भी हो सकती है। आपकी इस परेशानी का इलाज बेकिंग सोडा में छिपा है। खान-पान और सौंदर्य निखारने के लिए फायदेमंद बेकिंग सोडा आपकी इस परेशानी को दूर करने का बहुत कारगर उपाय है।

स्टैंडिंग साइड क्रंच करने का सही तरीका

स्टैंडिंग साइड क्रंच, ऑब्लिक मसल्स को लक्षित करने वाली स्टैंडिंग एब एक्सरसाइज है। इस एब एक्सरसाइज को अधिक प्रभावी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आप नियमित रूप से इस क्रंच को फर्श पर करें या अपने नियमित एब रूटीन में एक किस्म के रूप में जोड़ें। यह एक्सरसाइज आपको अधिक कैलोरी को जलाने, कोर स्ट्रेंथ को बनाने और आपके संतुलन में सुधार करने में मदद करती है। स्टैंडिंग साइड क्रंच के अंतर्गत कई अन्य प्रकार की मसल्स मूवमेंट भी शामिल होते है।

स्टैंडिंग साइड क्रंचेज पीठ के निचले हिस्से और गर्दन की मसल्स के लिए अच्छी तरह से काम करती है। इसमें गर्दन को स्ट्रेच करने या पीठ के बल लेटने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यह एब एक्सरसाइज के दौरान गर्दन में परेशानी या पीठ में दर्द अनुभव करने के कारण एब्डॉमिनल एक्सरसाइज से बचने वाले लोगों के लिए बेहतर होती है। यह एक्सरसाइज डांसर, फाइटर और अन्य एथलीटों के लिए आदर्श है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है जो फर्श पर आसानी से झुक और उठ नहीं सकते।

स्टैंडिंग साइड क्रंच कैसे करें?

- स्टैंडिंग साइड क्रंच को करने के लिए किसी भी उपकारण की जरूरत नहीं होती।
- इसे करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाए और वजन को अपने बाये पैर पर डाल दें।
- अब अपनी दाहिने घुटने को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ें।
- फिर अपने दाये पैर को शरीर के पीछे की तरफ उठाएं ताकी आपको घुटना समाने की ओर सीधा हो जाए।
- अब दोनों हाथों को सिर के पीछे लगा लें। सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी कोहनी को दाहिने घुटने के पास ले जाएं।
- फिर अपनी कोहनी और घुटने को इतना नजदीक ले जाने की कोशिश करें कि आपकी पसली और दाहिने कूल्हे पर प्रभाव महसूस हो।
- स्टैंडिंग साइड क्रंच को 15-15 क्रंचेज में दोनों तरफ से करें।

स्टैंडिंग साइड क्रंच के लाभ

- इससे गर्दन और पीठ के निचले हिस्से कम दबाव पड़ता है।
- मैट पर होने वाला यह साइड क्रंचेज अधिक कैलोरी जलता है।
- इसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, इसे आप कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं।
- हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के लिए अच्छी एक्सरसाइज है।

कार्यात्मक शरीर के विकास को बढ़ावा देता है।

टिप्स

- ऑब्लिक मसल्स को अधिक एक्टिव करने के लिए स्लो और कंट्रोल मूवमेंट करें।
- इस एक्सरसाइज को कार्डियों के लिए उपयोग करने के लिए, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए तेजी से रेप्स करें।
- एक्सरसाइज करते समय, हिप्स को आगे या पीछे स्विंग न करें।
- अपने सिर को हाथों के आगे या बगल से खींचने से बचें।
- रीढ़ की हड्डी को आगे झुकाने से बचें।

दवाओं के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए आसान तरीके

दवाएं कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हानिकारक बैक्टीरिया के खिलाफ मुकाबला करने, दर्द से राहत देने और जान बचाने में मदद करती है। दवाएं ऐसे रोगों का भी इलाज करती है जिनका अन्य किसी तरीके से इलाज नहीं हो पाता। लेकिन अफसोस, दवाओं के उपयोग में एक खामी भी है।

दवाएं मानव शरीर के साथ एक नाजुक संतुलन में काम करती हैं, लेकिन इस संतुलन के बिगड़ने पर यह कई प्रकार के साइड इफेक्ट का कारण बन सकती है।

साइड इफेक्ट

लगभग सभी प्रकार की दवाओं के साइड इफेक्ट होते है, लेकिन कुछ लोगों को साइड इफेक्ट का पता नहीं लगता वह इन साइड इफेक्ट के साथ आसानी से डील कर लेते हैं। यहां ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई है जो आपको पता होनी चाहिए।

किसे होते हैं साइड इफेक्ट

किसी को भी दवा से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक विशेष दवा आपके लिए साइड इफेक्ट का कारण नहीं हो सकता। यह दवा की खुराक, उम्र, लिंग, वजन और आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य दवाओं पर निर्भर करता है। बुजुर्गों में जवां लोगों की तुलना में साइड इफेक्ट अधिक होने की संभावना होती है।

कब्ज

कई निर्धारित और काउंटर दवा से कब्ज की समस्या हो सकती है। नियमित रूप से पेनकिलर दवाओं को लेने पर होने वाला यह सबसे आम दुष्प्रभावों में से एक है। हालांकि, आप ब्रान और होल वीट ग्रेन और हाई फाइबर सब्जियां और फल जैसे बींस, सेब और ब्रोकली के सेवन से इसका इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही तरल पदार्थों को खूब सेवन करें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें।

दिन के समय उनींदापन

कुछ दवाओं के कारण दिन में उनींदापन की समस्या भी हो सकती है, लेकिन शरीर द्वारा दवा के आदि होने पर समस्या आमतौर पर अपने आप ही दूर हो जाती है। अगर समस्या काफी दिनों तक ऐसी ही बनी रहती है तो डॉक्टर से पूछ कर दवा रात के समय लें। साथ ही यह भी सलाह दी जाती है कि उनींदापन महसूस होने पर भारी उपकरण न उठाये और ड्राइविंग करने से भी बचें।

सिरदर्द

कई निर्धारित और गैर निर्धारित दवाएं भी सिरदर्द का कारण हो सकती है। हालांकि शरीर को दवा की आदत हो जाने पर सिरदर्द अपने आप दूर हो जाता है। लेकिन अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहती हैं तो बिना देर किये अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

आमतौर पर दवा के लाभ मामूली साइड इफेक्ट से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अधिकांश दवाओं के साइड इफेक्ट अक्सर एक समय के बाद अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर साइड इफेक्ट लंबे समय तक रहते हैं तो आपको खुद से दवाओं को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर से इस विषय पर राय लेनी चाहिए। और अगर दवा लेने के बाद पित्ती, चेहरे, होठों और जीभ पर सूजन या सांस लेने में परेशानी महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

डायरिया

लगभग सभी दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में डायरिया की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि कीमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाएं जैसे एंटीबॉयोटिक, एंटी-डिप्रेसेंट और एंटासिड डायरिया का कारण बनती है। अगर आपको दवा से डायरिया की समस्या होती है तो अपने आहार में हल्के, फाइबर युक्त जैसे की चावल और दही को शामिल करें। और बेहतर महसूस होने तक मसालेदार और फैट से भरपूर खाद्य पदार्थों से बचें।

दिल को हेल्दी रखना है तो पियें ब्लैक टी

काली चाय वजन घटाने में मदद करती है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काली चाय दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। जी हां, एक नए शोध से यह बात सामने आई है कि काली चाय दिल को दुरुस्त रखने में बहुत मददगार होती है।

दिल के लिए काली चाय

काली चाय दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। एक ताजा शोध में यह बात सामने आई है। इस शोध में काली चाय में पाए जाने वाले एक विशेष तत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। काली चाय में प्रचुरता से पाया जाने वाला एक प्रकार का फलेवनॉयड, सर्टीन, धमनियों को ऑक्सीकरण से होने वाले नुकसान से बचाता है। साथ ही यह हृदयवाहिका से संबंधित बीमारियों की संभावना को भी कम करता है।

एंटीऑक्सीडेंट है फ्लेवनॉयड

फ्लेवनॉयड पौधों में पाए जाने वाले साधारण वर्णक यौगिक होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। विटामिन सी के असर को बढ़ाता है और रक्तवाहिकाओं के आसपास संयोजी ऊतकों की रक्षा करता है।

शोध के नतीजे

विश्वविद्यालय के बयान के मुताबिक वार्ड और क्रॉफ्ट ने कहा, भविष्य में हृदय रक्तवाहिकाओं पर फ्लेवनॉयड के असर से सम्बंधित अध्ययनों में अलग-अलग तरह के फ्लेवनॉयड और फ्लेवनॉयड के खाद्य स्त्रोतों के उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए।

क्या कहता है शोध

- प्रोफेसोरियल फेला, केविन क्रॉफ्ट ने चूहों पर किए गए एक प्रयोग के आधार पर कहा कि हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि सर्टीन, वाहिकाओं को ऑक्सीडेंट से होने वाले नुकसान से बचाने में सक्षम है।
- शोध पत्रिका बायोकेमिकल फॉर्मेकोलॉजी के मुताबिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बात के प्रमाण हैं कि खाद्य फ्लेवनॉयड्स उच्च रक्तचाप को कम कर सकता है और अथेरोस्क्लेरोसिस के विकास को कम कर सकता है।

घरेलू नुस्खों से मिल सकता है आराम

अब किडनी स्टोन के दर्द से मिलेगी राहत

किडनी में पथरी या स्टोन के दर्द को बर्दाशत करना काफी मुश्किल होता है, कोई भी व्यक्ति इस दर्द को ज्यादा देर तक बर्दाशत नहीं कर सकता है इसलिए कई डॉक्टर दवाइयां देकर इसे यूरीन के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर पथरी ज्यादा बड़ी हो तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप भी किडनी के स्टोन के दर्द से परेशान हैं तो कुछ घरेलू उपाय अपनाकर किडनी के स्टोन से राहत पा सकते हैं।

कैल्शियम से भरपूर खाना

तुलसी के पत्तों का सेवन करने से किडनी के स्टोन से छुटकारा पाया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को चबाना, तुलसी की चाय बनाकर पीना, तुलसी के रस में शहद मिलाकर पीने से स्टोन से राहत मिलती है। किडनी में स्टोन की समस्या से राहत पाने के लिए कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जो स्टोन को तोड़ने और बाहर निकालने में मदद करते हैं। दूध, मक्खन, तरबूज का सेवन करना लाभकारी साबित हो सकता है।

नींबू, ओलिव ऑयल और पानी

नींबू का रस चौथाई कप निकालकर उसमें उतना ही ओलिव आयल मिलाकर इसका सेवन करने के बाद पानी पीना चाहिए। दिन में 2 बार ऐसा करने से किडनी स्टोन से छुटकारा पाया जा सकता है। किडनी में स्टोन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दिन में कम से कम 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से किडनी में से स्टोन यूरीन के रास्ते बाहर निकल जाता है।

अनार और अजवाइन भी फायदेमंद

फलों का सेवन करना वैसे भी हमारी सेहत के लिए लाभकारी होता है, लेकिन स्टोन की समस्या होने पर अनार या अनार का जूस पीने से स्टोन से छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं अजवाइन का सेवन करने से पेट संबंधित कई रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन किडनी में स्टोन होने पर भी इसका सेवन कर सकते हैं।

लहरों के बीच बना सकते हैं बेहतर भविष्य

आजकल के बच्चे काफी सोच समझकर अपने कॅरियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन कई बच्चों को समुद्र की लहरों के बीच राफ्टिंग करना बेहद पंसद होता हैं अगर वो चाहें तो इस हॉबी को रोजगार का साधन भी बना सकते हैं, लेकिन इस कॅरियर की शुरुआत सिर्फ साहसी लोग ही कर सकते हैं और इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है।

प्रमुख संस्थान...

- इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, नई दिल्ली
- हिमालयन रिवर रनर्स, नई दिल्ली

कैसे करें शुरुआत...?

राफ्टिंग का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कई संस्थानों द्वारा करवाया जाता है। सबसे पहले प्रार्थी की शारीरिक जांच करने के बाद उसको राफ्टिंग गाइड के साथ खतरनाक राफ्टिंग ट्रैक पर भेजा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान रॉफ्टिंग उपकरणों के प्रयोग करने के बारे में समझाया जाता हैं और साथ ही यह जानकारी भी दी जाती हैं कि नदी में पानी के बहाव, उसकी गहराई की कैसे जांच करनी हैं। राफ्टिंग का सारा प्रशिक्षण लेने के बाद आप राफ्टिंग गाइड भी बन सकते हैं और पर्यटकों को राफ्टिंग का सफर करवा सकते हैं। हालांकि ये कॅरियर कमजोर दिलवालों के नहीं, बल्कि मजबूत इरादे वालों के लिए है। इसलिए ये कॅरियर चुनते समय आप ये डिसाइड कर लें कि कहीं आपको पानी से डर तो नहीं लगता।

रेसिपी

खट्टा मूंग

सामग्री

1 कप मूंग, 1 कप खट्टा दही, 1 टेबल-स्पून बेसन, 3/4 टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी-स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल-स्पून तेल, 1 टी-स्पून सरसों, 3 से 4 कड़ी पत्ता, 1/4 टी-स्पून हींग, 1/2 टी-स्पून अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, नमक स्वादअनुसार

सजाने के लिए: 2 टेबल-स्पून कटा हुआ हरा धनिया

परोसने के लिए: रोटली/ सादे चावल

विधि

मूंग को धोकर, उपयुक्त मात्रा के पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दें। छानकर, 11/2 कप पानी डालकर 2 सिटी के लिए प्रैशर कुक कर लें। ढ़क्कन खोलने से पुर्व सारी भाप निकलने दें। एक तरफ रख दें। दही, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को एक बाउल मे मिलाकर अच्छी तरह फेंट ले। एक तरफ रख दे। एक नॉन-स्टिक कढ़ाई मे तेल गरम करें और सरसों, कड़ी पत्ता, हींग और अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डालें। जब बीज चटकने लगे, पका हुआ मूंग डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आंच पर 30 सेकन्ड तक पका कें। दही-बेसन का मिश्रण, नमक और 11/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें और बीच में एक बार हिलाते हुए, मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लें। धनिया से सजाकर सादे चावल या रोटली के साथ गरमा गरम परोसें।

कोवालम मटर

सामग्री

1 1/4 कप उबले हुए हरे मटर, 1 टेबल-स्पून तेल, 1/2 टी-स्पून जीरा, 1 टी-स्पून उड़द दाल, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टी-स्पून लहसून की पेस्ट, 1 टी-स्पून धनिया-जीरा पाउडर, 1 टी-स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टी-स्पून हल्दी, 1/2 टी-स्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक, स्वाद अनुसार, 1 टेबल-स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पीस कर नारियल-काजू की मुलायम पेस्ट बनाने के लिए (थोड़े पानी का उपयोग करते हुए), 4 टेबल-स्पून कसा हुआ नारियल, 1 टेबल-स्पून टुकड़ा किया हुआ काजू

विधि

एक नॉन-स्टिक कढाई में तेल गरम करिए और उसमे जीरा और उड़द दाल डालिए। जब जीरा चटखने लगे, तब उसमे प्याज डालिए और मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट भूनिए। उसमे लहसून की पेस्ट, धनिया-जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, टमाटर, नमक और 2 टेबल-स्पून पानी डालिए, अच्छे से मिलाइए और मध्यम आंच पर 2 मिनट, बिच-बिच में हिलाते हुए पकाइए। उसमे बनाया हुआ नारियल-काजू के पेस्ट, हरे मटर, धनिया और 1/2 कप पानी डालिए, अच्छे से मिलाइए और मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट, बिच-बिच में हिलाते हुए पकाइए। गरमा गरम परोसिए।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**